विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली। सोमवार, 27 जनवरी 2025

बड़ी कामयाबी

26/11 यानी मुंबई आतंकी हमले के बहुचर्चित आरोपी तहव्वुर राणा का अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद उसके प्रत्यर्पण की राह खुल गई है। यह भारत की एक अहम कूटनीतिक और कानूनी जीत तो है ही, आतंक के कारोबारियों को न्याय की वेदी पर ला पटकने के वैश्विक अभियान के लिहाज से भी एक बड़ा कदम है।

26/11 : राणा का प्रत्यर्पण तय

आतंक का बर्बर चेहरा | 2008 का मुंबई आतंकी हमला न केवल देशवासियों को स्तब्ध कर देने वाला था बल्कि इसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। जिस तरह समुद्री मार्ग से आए लश्कर-ए-तैयबा के दस आतंकवादियों ने भारत की वित्तीय राजधानी को बंधक सा बना लिया और यहां तीन दिनों तक आतंक का खेल खेलते रहे, उसे भुलाना मुश्किल है। इस हमले से जुड़े कई आतंकी इस दौरान मारे भी जा चुके हैं, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था का सामना करने की जहां तक बात है तो कसाब के बाद तहव्वुर राणा दूसरा प्रमुख चेहरा होगा।

परदे के पीछे का सच | आतंक के इस खेल में मोहरे बने लोग भले सामने नजर आते हों, उनकी भूमिका नगण्य ही होती है। असल भूमिका इन्हें परदे के पीछे से बढ़ावा देने वाले उन लोगों की होती है जो आम तौर पर परदे के पीछे ही बने रहते हैं। तहव्वुर राणा का यह प्रत्यर्पण इस लिहाज से भी अहम है। वह न केवल मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रहा बल्कि कनाडा जा बसने से पहले पाकिस्तान आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर भी काम करता रहा है। आश्चर्य नहीं कि 26/11 केस में पब्लिक प्रॉसीक्यूटर रहे उज्ज्वल निकम समेत कई लोग मानते हैं कि यह प्रत्यर्पण इस मामले में पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े अफसरों की भूमिका पर भी बेहतर ढंग से रोशनी डाल सकता है।

आगे की चुनौतियां | ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाली चुनौतियों की गंभीरता को समझते हुए एक-एक कदम फूंक-फूंक कर बढ़ाया जाए। राणा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और तमाम अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए आगे बढ़ना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है कूटनीतिक मोर्चे पर सावधानी बनाए रखना। तभी इस मामले की अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़ी तमाम परतों को खोलना और इसमें शामिल सभी तत्वों को बेनकाब करना संभव हो पाएगा।

चक्र-व्यू

जारी है लूट

राहुल पाण्डेय

अगर दुनिया को उत्तर-दक्षिण में बांटे तो इतिहास में हुए युद्धों में दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहली, आक्रमणकारी आए, और यहीं दफन हुए। दूसरी, उत्तरी हिस्से के युद्ध अंतहीन लूट की वो नहर बने, जो आज तक बह रही है। पिछले हफ्ते दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक के मौके पर जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट यही कहती है। इसके मुताबिक 1765 से 1900 के बीच अंग्रेज भारत से लगभग 648.2 खरब डॉलर की संपत्ति लूट ले गए। इतना कि पूरा लंदन नोटों से ढक जाए। 1750 में दुनिया के कुल औद्योगिक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25 फीसदी था। कॉलोनी बनने के बाद 1900 आते-आते घटकर यह महज 2 फीसदी रह गया। आज भले हमारी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ने को तैयार हो, औद्योगिक उत्पादन में हमारा हिस्सा 1750 के लेवल के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है।

कॉलोनी शब्द लैटिन के कोलोनस से निकला है जिसका अर्थ है- एक छोटा खेत। कॉलोनी यानी उस पर कब्जा। दुनिया के उत्तरी हिस्से ने ताकत के बल पर अपने साम्राज्य बढ़ाए। आगे चलकर ये उनकी कालोनियां बनीं, जिसमें जन्मे सुक्खी लाला जैसे सूदखोर। एडवर्ड सईद कहते थे कि दक्षिण इस मायने में उत्तर से अलग है कि दक्षिणी देश किसी दूसरे देश को इस तरह से नहीं चूसते। अपनी किताब द नटमेग्स कर्स में लेखक अमिताव घोष कहते हैं कि उपनिवेशवाद, नरसंहार और संगठित हिंसा की नींव पर औद्योगिक आधुनिकता का निर्माण हुआ, और उत्तर-औपनिवेशिकता उसी की निरंतरता है। दावोस में आई रिपोर्ट भी यही कहती है कि उत्तर आज भी दुनिया के दक्षिणी हिस्सों को अलग-अलग तरीके से लूट रहा है। मसलन, 1970 से 2023 तक ग्लोबल साउथ की सरकारों ने ग्लोबल नॉर्थ के सुक्खी लालाओं को 3.3 ट्रिलियन डॉलर महज ब्याज दिया। यानी लाला ने लूट की रकम दक्षिण को वापस कर्ज में दी और उस पर ब्याज वसूला। ऑक्सफैम ही नहीं, सईद, घोष और एकाध जगहों पर बीएस नायपॉल ने भी कहा है कि असमानता और लूट के जो सिद्धांत उपनिवेशवाद में विकसित हुए थे, आज भी आधुनिक जीवन को आकार दे रहे हैं। लूट की यह नहर आज भी बह रही है, और उसी दिशा में बह रही है- यानी दक्षिण से उत्तर की ओर।

एकदा

ठंड में दंड-बैठक

तब देश में अंग्रेजों का शासन था। उनके अत्याचार से हर तरफ लोग परेशान थे। स्वतंत्रता संग्राम अभी अपने शुरुआती दौर में था। उन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक बार एक अंग्रेज अफसर किसी निर्दोष भारतीय के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। लगभग सात आठ वर्ष का एक बालक पास खड़ा यह सब देख रहा था। उस बालक को अंग्रेज के व्यवहार से बहुत गुस्सा आया। उसने झट से एक पत्थर उठाया और पुलिस अफसर को दे मारा। अफसर को चोट आई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब वह बालक पकड़ा गया तो उस पुलिस अफसर ने बच्चे को कड़ाके की ठंड में खुले मैदान में रात भर नंगा खड़ा रहने की सजा दी और निगरानी के लिए दो चौकीदार नियुक्त कर दिए गए। ठंड में कंबल में दुबके चौकीदार शीघ्र ही खर्राटे भरने लगे। आधी रात में जब उनकी नींद खुली, तो वे देखकर हैरान रह गए कि वह बालक दंड-बैठक लगा रहा था और उसके शरीर से लगातार पसीना बह रहा था। इस वीर और निडर बालक का नाम था चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया। उन्हें आजादी जान से ज्यादा प्यारी थी। 'मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, और आजाद ही मरूंगा।' ऐसी उनकी सोच थी।

संकलन : दीनदयाल मुरारका

विधानसभा चुनाव दूर हैं, लेकिन राज्यहै में सियासी समीकरण अभी से बनाए जा रहे हैं

एक मुलाक़ात ने बदली बिहार की तस्वीर

प्रियरंजन भारती

बिखराव की खबरों के बीच विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. के लिए बिहार से राहत के संकेत हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल में बिहार पहुंचे तो बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से भी मुलाकात की। इस एक घटना ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को टर्निंग पॉइंट पर ला खड़ा किया है।

झटके पर झटका | दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग-अलग उतरने के कारण I.N.D.I.A. में फूट की खबरें चल पड़ी थीं। कांग्रेस के लिए यह झटका था कि गठबंधन के साथियों ने दिल्ली में समर्थन देने के लिए उसके बजाय AAP को चुना। इससे पहले, पार्टी इसलिए भी सकते में थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन को लीड करने की ख्वाहिश जताई और लालू समेत कई विपक्षी नेताओं ने उन्हें सपोर्ट किया।

खुशी गायब | ये सारी घटनाएं बिहार में चुनावी तैयारी में लगे NDA की बांछें खिलाने के लिए काफी थीं। लेकिन, राहुल और लालू परिवार की मुलाकात ने विपक्षी कुनबे को मजबूती दे दी है। जिन्हें लग रहा था कि विपक्ष बिखरने वाला है, वे अब इस एक मुलाकात के बाद चिंता में घिरे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी संवाद यात्रा पर हैं। वह रोज नए वादों का पिटारा खोल रहे हैं और NDA नेताओं की हर बात का पलट कर जवाब देते हैं।

लालू का असर | BJP, NDA और नीतीश का डर बेवजह नहीं है। लोकसभा चुनाव में लालू यादव की चुनावी रणनीति ने NDA को मुश्किल में डाल दिया था। लालू ने ऐसी बिसात बिछाई कि NDA के गढ़ और उसके वोटबैंक में भी सेंध लगा दी। BJP-JDU को मध्य बिहार में नाकों चने चबाने पड़े थे। यह लालू यादव की सभी सियासत के दांव माने गए कि मध्य बिहार में औरंगाबाद से सासाराम तक BJP के गढ़ ढह गए। इसी तरह का डर फिर हावी है। फिर, नीतीश कुमार के एक और पलटी मारने की आशंका भी खड़ी हुई थी।

नए दांव | लोकसभा चुनाव में RJD के MY (मुस्लिम-यादव) समीकरण से इतर 'बाप' का नारा भी दिया गया। तेजस्वी यादव ने समीकरण में सुधार करते हुए पिछड़ों, अगड़ों और गरीबों को एकजुट करने का नारा दिया, लेकिन यह चल नहीं पाया। विधानसभा चुनाव में और नए दांव चलने के आसार अधिक नजर आने लगे हैं।

पीके फैक्टर | चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बहुत उम्मीदें जगा कर जन सुराज पार्टी का गठन किया है। पिछले साल विधानसभा उपचुनाव में पीके ने सीट तो एक भी नहीं जीती, लेकिन वोटों के समीकरण उलट-पुलट दिए। नतीजे में I.N.D.I.A. को करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे यह नैरेटिव भी बना है कि पीके की पार्टी BJP की चुनावी चालबाजी का ही एक हिस्सा है और वह लालू यादव व नीतीश कुमार को कमजोर करने वाली कड़ी साबित होंगे।

भूमिका बदली | पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने NDA से अलग होकर चुनाव लड़ा था। कहा गया कि BJP की शह पर उन्होंने JDU का नुकसान किया। चिराग फिर से NDA का हिस्सा है और नीतीश से रिश्ते बेहतर बन चुके हैं। लेकिन,इस बार चिराग वाली भूमिका में पीके हो सकते हैं।

पशुपति को सहारा | राज्य में जनाधार विकसित करने और समीकरण साधने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। I.N.D.I.A. नई कड़ियां जोड़ता दिखाई दे रहा है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस की लालू यादव से मुलाकात के बाद लग रहा है कि उन्हें सहारा मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव में भतीजे चिराग पासवान के आगे BJP ने चाचा पशुपति को महत्व न देकर हाशिए पर डाल दिया था। इसी तरह, VIP पार्टी के नेता मुकेश सहनी महागठबंधन के नए पार्टनर तय हो गए लगते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा अलग मोर्चा बनाए चल रहे थे, पर इस बार वह NDA में हैं।

सियासी तिलिस्म | सीटों के तालमेल का स्वरूप बाद में तय होगा है, पर लालू परिवार से राहुल गांधी की भेंट ने सारे कयासों पर पानी फेर दिया है। यह तय हो गया है कि कांग्रेस को पिछलग्गू बनाए रखकर चलने में माहिर लालू यादव उम्मीद के मुताबिक उसे और नहीं डराने जा रहे। वहीं, कांग्रेस भी उसी भाव में पीछे चलने से परहेज नहीं करेगी। लालू-तेजस्वी का यही तिलिस्म कांग्रेस को रास आता है और यही बिहार के चुनावी गणित पर छाप भी छोड़ जाता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

संगम पर जन्म लेते हैं नए रंग और नई शक्ति

धराली वाले मानते हैं कि पिंडर को काबू में नहीं किया जा सकता। उसके पानी को बंधना पसंद नहीं। लेकिन, कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद पिंडर उस शांत गंगा का हिस्सा बन जाती है, जिससे किसी को डर नहीं लगता। यही संगम है- विभिन्न प्रवाहों, रंगों और शक्तियों का मिलन। ऐसी जगह, जहां अलग-अलग दिशाओं से बहती नदियां एक होकर नई यात्रा शुरू करती हैं। जहां ईश्वर की रची दो ताकतें मिलकर एक नई ताकत बनती हैं। संगम बस नदियों का मिलना नहीं, यह जीवन, सामंजस्य और एकता का प्रतीक है।

भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी माना गया है और संगम को शुद्धि व पवित्रता हासिल करने का स्थान। मान्यता है कि संगम पर स्नान करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जुटा लाखों का जनसैलाब स्वीकृति है इस बात की। एक तरफ मानव इतिहास की तीन प्राचीन नदियों का संगम और ठीक उसके सामने उसके किनारे पर पली-बढ़ी विभिन्न भाषाओं, रीति-रिवाजों और खानपान का संगम। एक तरफ सफेद पानी, दूसरी ओर गहरा नीला रंग। यह कलाकारी प्रकृति की है। ऐसा लगता है कि देवताओं ने खुद कूंची उठाई होगी। ऐसा ही अद्भुत नजारा दिखता है अमेरिका में ग्रीन और कोलोराडो नदी के मिलन स्थल पर, जहां हरा और भूरा पानी एक होता है। या

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

चीन के चूंगचींग में, जहां साफ पानी वाली Jialing मिट्टी लिए बड़ रही Yangtze से मिलने दौड़ पड़ती है। या जिनेवा में, जहां रोन और आर्वे एक होती हैं। भले ही सभी जगह का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व न मिलता हो, लेकिन प्रकृति अकेली कारण है संगम की विशिष्टता के लिए।

संगम है भिन्न रास्तों, भिन्न विचारों और भिन्न संस्कृतियों का एक साथ आना। इसमें मिलकर भी बजूद खोता नहीं, एक के भीतर दूसरा जीवित रहता है। प्रयागराज के बाद यमुना दिखती भले न हो, लेकिन महसूस करने वाले बनारस के गंगाजल में भी महसूस कर सकते हैं उनकी धड़कन।

संगम मिल जाना है और सभी को अपनाना भी। बड़े-बड़े शहरों से होकर गुजरती कोई विशाल नदी कभी किसी छोटी जलधारा को इनकार नहीं करती। यमुना से मिलने के बाद भी गंगा बांहें फैलाए स्वागत करती हैं उन सभी छोटी-छोटी नदियों का, जो रास्ते में उनसे मिलती जाती हैं। गंगा विशाल हृदय दिखाती हैं, लेकिन वे नदियां भी कम विशाल नहीं, जिन्होंने किसी बड़े काम के लिए खुद को विलीन कर दिया। अकेले सागर तक का सफर किसी के लिए आसान नहीं होता।

संगम पर बैठकर बहती नदियों को देखना और उनकी धारा के संगीत को सुनना ध्यान लगाने जैसा है। यहां अहसास होता है सृष्टि की विशालता का। यहां आप अपने विचारों को स्थिर कर सकते हैं और प्रकृति से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि यहीं उन सवालों के जवाब भी मिल जाएं, जिन्हें आप वैसे न खोज पाएं।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की हिंदगयों के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें- 'जीवन आनंद'

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

सचाई की नैया हिलेगी-डुलेगी, पर डूबेगी नहीं

ब्रह्म कुमारी शुक्ला

हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन शांतिपूर्ण, संतोषप्रद और खुशहाल हो, लेकिन इसके लिए सुख-साधनों का होना ही काफी नहीं है। असल में, जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन की सच्चाई को समझते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। आप सच पर कायम रहें तो आपका मन सदा खुशी से नाचता है। सच्चा व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल, सत्य की जीत होनी ही है। सत्य की नैया हिलेगी-डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं।

सचाई अंतरात्मा का न केवल श्रेष्ठ गुण है, बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, फिर भी कइयों ने सत्य को ईश्वर माना है। इस संदर्भ को इस गीत से समझ सकते हैं- ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। परमात्मा शिव न केवल सदाशिव हैं, बल्कि संसार में सुंदरता और आनंद के संस्थापक हैं। सत्य तीन प्रकार के हैं- भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक। फूल का खिलना, सूर्य का उगना और अस्त होना, पानी का उबलना- ये सब भौतिक सत्य हैं। हम जो कहते हैं, वही करें, दूसरों के प्रति करुणा और समझदारी दिखाएं, हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करें और किसी के साथ अन्याय न करें तो भी हम सच के साथ हैं। यह नैतिक सत्य है। आध्यात्मिक सत्य आत्मा, ब्रह्म या अस्तित्व की सच्चाई को पहचानने की प्रक्रिया है।

सत्य को जानना, मानना और अपनाना सहज नहीं है। आज के दौर में सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक से एक जटिल समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। उन्हें तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति सत्य और ईश्वर पर अडिग विश्वास और आस्था रखता है, उसका मन हमेशा सच्चाई, शांति, संतुष्टि और साहस से भरा रहता है। इस विश्वास के साथ वह अपने प्रयासों को सरल, सहज ढंग से बिना किसी बड़ी बाधा के सफलता की ओर बढ़ाता है। कहते हैं, सच्चा इंसान वही है जो अहंकार का अंत कर पाता है। सत्य के ज्ञान और उसकी शक्ति के जरिए वह सही आत्मबोध कर पाता है। ऐसा व्यक्ति सच्चे और अच्छे लोगों की कदर करना जानता है और सबसे शालीनता से पेश आता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा दुआओं का बल मिलता है।

ऐसे व्यक्ति सदा स्वतंत्र होते हैं, किसी भी बंधन से बंधे नहीं होते हैं। एक स्वाधीन आत्मा के रूप में, वे सब प्रकार के देह भान व देह अभिमान से मुक्त रहते हैं।

सुकरात की नज़र से कभी देखा है

मृत्युंजय राय

50 वर्ष की उम्र में मशहूर लेखक लियो टॉल्सटॉय को प्रेम, बच्चों और दुनियावी कामयाबी को लेकर लगा था कि क्या वाकई इन चीजों का कोई अर्थ है? 'OPEN SOCRATES: The Case for a Philosophical Life,' किताब की शुरुआत एग्नेस कैलार्ड टॉल्सटॉय के इसी संदेह से करती है। एग्नेस लिखती हैं कि सेल्फ-इंप्रूवमेंट को अक्सर इच्छाशक्ति से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन असल में यह आइडियाज की बात है। वह लिखती हैं- ऐसा नहीं कि इंसानों में इच्छाशक्ति की कमी है। ऐसा नहीं कि अच्छा क्या है, लोग इसे जानते हैं, फिर भी उसे पाने की कोशिश नहीं करते। एग्नेस का कहना है कि असल में अच्छा क्या है, इस बारे में हमने बहुत गंभीरता से चिंतन किया ही नहीं होता है। वह बताती हैं- एक अच्छा और नैतिक इंसान बनने की खातिर संघर्ष करना हकीकत में एक बौद्धिक काम है।

विचार विंडो

एग्नेस यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में फिलॉस्फी पढ़ाती हैं। वह रीडर्स को बताती हैं कि दार्शनिक जीवन किस तरह से गुजारा जा सकता है। कैसे लोग अधिक स्वतंत्र और बेहतर रोमांटिक बन सकते हैं। कैसे वे अधिक साहसी हो सकते हैं। और, इन सबके बारे में सुकरात से क्या सीखा जा सकता है।

असल में, सुकरात किसी चर्चा में सामने वाले को आखिरी वक्त तक चुनौती देते रहते थे। उनकी कोशिश होती थी कि सामने वाले व्यक्ति ने जो नजरिया रखा है, क्या वह उसे समझता भी है? क्या उसने जो बात कही है, वाकई वही कहना चाहता था? सुकरात को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उन्होंने एक समय कहा था, 'मैं अलोकप्रिय होता जा रहा हूं। मुझे इसका एहसास है।' यह बात सही भी थी। ग्रीस के कई ताकतवर नेताओं को उन्होंने खुद से दूर कर दिया था। आखिरकार जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तो इन ताकतवर लोगों ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। सुकरात 399 ईसा पूर्व में दुनिया से चले गए। उनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है और उनके विचारों के बारे में भी। फिर उनके विचारों पर एक और किताब की जरूरत क्या थी? इस सवाल के जवाब में एग्नेस लिखती हैं कि अक्सर सुकरात के विचारों को नरमी के साथ रखा जाता है। उनके मुताबिक, सुकरात के विचारों को क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाने वाला बताया जाता है। यहां केंद्र में क्रिटिकल थिंकिंग है, लेकिन एग्नेस लिखती हैं कि सुकरात के विचार इतने गंभीर हैं कि केंद्र में उन्हें ही होना चाहिए। वह लिखती हैं कि इन विचारों की गहराई को ठीक से समझा जाए तो वे आपको बेहद क्रांतिकारी लगेंगे।

पढ़ाई के दिनों से ही सुकरात, एग्नेस को बहुत पसंद थे। वह इस किताब में लिखती हैं कि ग्रीक महान दार्शनिक से आप जीवन भर सीखते रह सकते हैं। 'Open Socrates,' में जीवन-मृत्यु का प्रश्न भी आया है। सुकरात ने कहा था कि दर्शन असल में मृत्यु के लिए खुद को तैयार करना है और यह बात लेखिका एग्नेस कैलार्ड को बिल्कुल सटीक लगती है।

चरित्र हनन के ख़िलाफ़

प्रणव प्रियदर्शी

बात चाहे परिवार की हो या बिरादरी और समाज की या फिर किसी पेशे की, स्वतंत्र सोच वाली लड़कियों के रास्ते की एक बड़ी चुनौती होती है चरित्र हनन की कोशिशें। इस लिहाज से देखा जाए तो उड़ीसा हाईकोर्ट का हाल में आया वह फैसला काफी अहमियत रखता है जिसमें कोर्ट ने पति के दावों को खारिज करते हुए पत्नी को राहत दी है। पहली नजर में फैसला सिर्फ गुजारा भत्ता से जुड़ा लगता है, लेकिन गौर किया जाए तो इसके निहितार्थ काफी दूर तक जाते हैं। मामला मूलतः ऐसे कपल का है जिसमें शादी के चार महीने के अंदर पत्नी ने घर छोड़ दिया। पति का कहना था कि पत्नी ने अपनी मर्जी से और बिना किसी ठोस कारण के घर छोड़ा। इसलिए उसे गुजारा भत्ता पाने का हकदार नहीं माना जा सकता। 5 मई 2021 को शादी के बाद पति के साथ रह रही लड़की ने 28 अगस्त 2021 को घर इसलिए छोड़ा क्योंकि पति उसके चरित्र पर लांछन लगाया करता था। उसका आरोप था कि इस लड़की के दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध हैं। हालांकि वह इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं देता था। अदालत ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि कोई भी स्वाभिमानी लड़की इस तरह के निराधार आरोप सहन नहीं कर सकती। यह उसकी गरिमा पर हमला होता है। ऐसे में अगर पत्नी ने घर छोड़ने का फैसला किया तो यह सर्वथा उचित है और पति के दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है, फैमिली कोर्ट के फैसले के मुताबिक पति को अब उसे 3000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देना होगा। यह फैसला उन तमाम लड़कियों को ताकत देगा जो किसी भी फील्ड में इस तरह के निराधार आरोपों का सामना करती हैं और उन्हें चुनौती देने का जज्बा रखती हैं।

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ **महिलाओं की जिम्मेदारी**

25 जनवरी का लेख 'कैसे सताई जा रही हैं औरतें' पढ़ा। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, कितने भी बड़े पद पर हों, घर की जिम्मेदारी अमूमन उन्हीं के सिर पर रहती है। शादी के बाद कहीं आने -जाने से पहले उन्हें परिवार की इजाजत लेनी होती है। यहां तक कि घर की रसोई की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। बच्चों के होम वर्क पूरे करवाना, घर आए मेहमानों का आगत-स्वागत करना उनके हिस्से में है। आज भी भारतीय पुरुष महिलाओं पर अपना हक मानते हैं। पारिवारिक मर्यादा के दायरे में रहने वाली महिलाओं को ही सराहा जाता है।

मीना धानिया, सिरसपुर

■ **आराम के बाद काम**

'जीवन आनंद' कॉलम में 20 जनवरी का लेख 'कुछ न करना भी बहुत बड़ा काम है' में आजकल की व्यस्त जीवनशैली के खिलाफ एक मजबूत और संतुलित दृष्टिकोण दिया गया है। लेखक ने बताया कि कभी-कभी कुछ नहीं करना, यानी खुद को आराम और मानसिक शांति देना, हमारे मानसिक स्वास्थ्य और रचनात्मकता के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल हम कार्यों और उत्पादकता के दबाव में जी रहे हैं, जहां व्यस्त रहना ही सफलता का प्रतीक माना जाता है।

सुधीर भंडारी, रोहिणी

जीवन आनंद

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

देश के कई टोल प्लाजा पर नकली पर्ची का खेल : एक खबर - पर्ची नकली होगी, मिलीभगत तो असली होती है।

कविता सिंह

नवभारत टाइम्स, ए. 8,9,10,11 सफदरजंग एन्क्लेव | विनोद अग्रवाल के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली | सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित | प्रधान संपादक : **राजकुमार अनिल ईश्वर देव, समूह संपादक, अतिरिक्त प्रधान संपादक** और चीफ मेनेजर ए.के. मेहता द्वारा प्रकाशित | मुद्रक : प्रिंटवेल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 3, सेक्टर 58-59, इंडस्ट्रीज़ एरिया, हिमाचल मीडिया एजेंसीज़, गाजियाबाद से मुद्रित | फोन : 2360000 | फैक्स : 2360001, मेट्रोपोल्स मार्केटिंग : 1 एडवर्ड मिलिंग रोड, मुंबई-400001 | फैक्स के लिए मुद्रक : 1 व. बी. सोसाइटी | नेपाल में मुद्रण : संगम ले मीडिया - नेपाल 8 व. - मीडिया - नेपाल, 8 व. - मीडिया (रिपोर्ट पत्रकार) : आनंद भारती | इस अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के प्रभार एवं संपादन दिनु मिश्रा, एस. के. मेहता के उत्तरदायित्व में।

हिन्दुस्तान 1936

विशेष वेधशाला

भारत में सौर मंडल संबंधी शोध का इतिहास पुराना है। सूर्य के साथ हमारा संबंध और उसे समझने की अभिलाषा आदिकाल से सतत जारी है। इसी संदर्भ में बेंगलुरु में सौर वैज्ञानिकों का विशाल सम्मेलन स्वागतयोग्य है। यदि आधुनिक इतिहास की बात करें, तो आज से 125 साल पहले दक्षिण भारत में कोडाइकनाल सौर वेधशाला (केएसओ) की स्थापना हुई थी। यह एक ऐसा अवसर था, जब अंग्रेजों ने भी भारत में सूर्य पर होने वाले शोध के महत्व को समझा था और इसके साथ ही भारत में आधुनिक सौर खगोल विज्ञान और भौतिकी का जन्म हुआ था। बेंगलुरु में दुनिया भर के करीब 200 वैज्ञानिकों ने मिलकर कोडाइकनाल सौर वेधशाला की स्थापना का जश्न मनाया है और पांच दिन तक सूर्य व सौर मंडल से जुड़े विविध विषयों पर उपयोगी चर्चा हुई है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के लिए कोडाइकनाल सौर वेधशाला (केएसओ) की 125वीं वर्षगांठ विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की दृष्टि आदित्य एल वन अभियान पर भी टिकी है। सूर्य को यथासंभव करीब से देखकर समझने की चेष्टा की वजह से भी ऐसे वैज्ञानिक सम्मेलन का महत्व बहुत बढ़ जाता है।

इस सम्मेलन में अंतरिक्ष के मौसम और सूर्य से तारों के जुड़ाव पर कारगर चर्चा हुई है। ध्यान देने की बात है कि पिछले 125 वर्ष से यह वेधशाला सूर्य की छवियों का संग्रह कर रही है। इसके पास सूर्य की छवियों का विशाल भंडार बन गया है और इनके माध्यम से भी सूर्य में हो रहे बदलावों को रेखांकित किया जा सकता है। सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने में इस वेधशाला का खास योगदान माना जाता है। केएसओ देश में आधुनिक सौर खगोल भौतिकी का अग्रदूत रहा है। यह अच्छी बात है कि केएसओ के पूरे ज्ञान भंडार का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसके बाद दुनिया में कहीं भी किसी के लिए सूर्य पर अध्ययन करना आसान हो जाएगा। भारत में वेधशालाओं पर निरंतर काम हो रहा है और इसी कड़ी में लद्दाख में पैंगोंग त्सो के तट पर मराक में प्रस्तावित नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप स्थापित करने के प्रयास उत्साह बढ़ाते हैं। लद्दाख एक ऊंची और स्वच्छ जगह है, वहां से सूर्य के अध्ययन में वैज्ञानिकों को विशेष सुविधा होगी। लद्दाख को एक नया वैज्ञानिक संस्थान मिलेगा, जिससे वहां भी विज्ञान को बल मिलेगा। इस विशाल प्रस्तावित टेलीस्कोप की वजह से भारतीय वैज्ञानिकों में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

वैज्ञानिकों और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के लिए कोडाइकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ विशेष महत्व रखती है।

इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईए की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ए एस किरण कुमार ने इस सम्मेलन के अवसर पर कहा है कि इसरो के पास अंतरिक्ष से सौर भौतिकी अनुसंधान में मदद करने की सभी क्षमताएं हैं, जिनका उपयोग होना चाहिए। खास यह है कि वैज्ञानिक किरण कुमार ने आम लोगों का भी आह्वान किया है कि वे सूर्य पर शोध संबंधी किसी नए विचार के साथ सामने आएं, कोई नया उपकरण बनाएं, तो इसरो सहयोग करने को तैयार है। यह सुखद पक्ष है कि भारत में स्वतंत्र वैज्ञानिकों को भी इसरो हरसंभव सुविधा मुहैया कराता है। सौर शोध संबंधी कोई उपयोगी उपकरण या सैटेलाइट अगर कोई तैयार करे, तो उसे लॉन्च करने के लिए इसरो तैयार है। भारतीय वैज्ञानिकों को आशा है कि बेंगलुरु में आयोजित सम्मेलन से विश्व स्तर पर भी वैज्ञानिकों के बीच सहयोग बढ़ेगा।

दिल्ली चुनाव में चुनौती बढ़ाता एआई

अब जब राजधानी में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया ने आधी दूरी तय कर ली है, तब चुनाव आयोग से एआई के इस्तेमाल को लेकर आए दिशा-निर्देश कितने अर्थपूर्ण साबित होंगे?

वहां स्कैन करें

हरजिंदर | वरिष्ठ पत्रकार

चुनाव आयोग ने बहुत देर कर दी। चुनाव प्रचार में कृत्रिम बुद्धि, यानी एआई के इस्तेमाल को लेकर आयोग ने जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा इस महीने की शुरुआत में हुई, लेकिन प्रचार तो बहुत पहले से चल रहा है। एआई का इस्तेमाल भी शुरू से ही हो रहा है। यह भी कहा जा रहा था कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव देश का ऐसा पहला चुनाव बन गया है, जहां बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके इस्तेमाल को लेकर उठाने वाले नैतिक सवाल भी लगातार खड़े किए जा रहे हैं। मगर दिशा-निर्देश जैसी कोई स्पष्ट बाध्यता न होने के कारण हर कोई अपने-अपने ढंग से इस काम को कर रहा था।

पिछले साल जनवरी में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग एआई और डीपफेक के दुरुपयोग को लेकर पूरी तरह सतर्क है। बाद में जब चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के फेक वीडियो का मामला सामने आया, तो आयोग ने उस पर सक्रियता भी दिखाई थी। इसी वजह से यह उम्मीद बनी थी कि चुनाव आयोग दिल्ली में विधानसभा घोषणा के साथ एआई के बारे में कुछ प्रावधान करेगा। जैसे चुनावी विज्ञापनों, प्रचार वगैरह को लेकर स्पष्ट नियम-कायदे हैं, उम्मीद थी, वैसा ही कुछ निर्देश प्रचार सामग्री में एआई के इस्तेमाल को लेकर भी सामने आएगा। लेकिन उस वक्त आयोग ने कुछ नहीं किया। अब जब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया ने आधी दूरी तय करली है, तो जो दिशा-निर्देश सामने आए हैं, वे कितने अर्थपूर्ण साबित होंगे, कहा नहीं जा सकता।

इन दिशा-निर्देशों पर गौर करने से पहले यह देखना जरूरी है कि राजधानी के चुनाव प्रचार में एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? दुनिया भर में एआई तकनीक इस समय जिस स्तर पर पहुंच चुकी है, उसके मुकाबले दिल्ली में इसका इस्तेमाल प्रारंभिक स्तर का है, तो कुछ

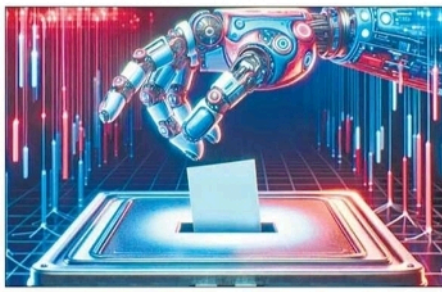

मामलों में यह बचकाना भी लगता है। यह मूलतः वीडियो बनाने तक सीमित है।

सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एआई से तैयार जो वीडियो जारी किए हैं, उनमें सबसे चर्चित हैं, अमेजन प्राइम के लोकप्रिय धारावाहिक *पंचायत* के पात्रों पर बनाए गए वीडियो। भाजपा के वीडियो में इस धारावाहिक के दो पात्र, भूषण और बिनोद आपस में बातें कर रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किस तरह लोगों को ठग रहे हैं। दूसरी ओर, आप के वीडियो में इसके पात्र एक-एक करके आते हैं और दिल्ली की जनता को क्या-क्या मिल रहा है, यह गिनवाते हैं, साथ ही इसमें भाजपा के लिए 'धत' भी है। धारावाहिक के कुछ पात्र ऐसे हैं, जो दोनों ही पार्टियों के प्रचार में दिख रहे हैं।

कई लोकप्रिय फिल्मों के दृश्यों को भी एआई से बदलकर सोशल मीडिया में विज्ञापन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप के एक वीडियो में फिल्म *चक दे इंडिया* का वह दृश्य है, जिसमें शाहरुख खान महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को कुछ समझा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उसकी जगह जो 'वॉयसओवर' डाला है, उसमें वह लड़कियों से कह रहे हैं कि 23 दिसंबर को सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए।

धारावाहिक या फिल्म के दृश्य तो जस के तस उठाए गए हैं, लेकिन उन पर सिर्फ 'वॉयसओवर' ही नहीं चस्पां किया गया, इन पात्रों के लब-ओ-लहजे, यानी 'लिपसिंक' का संवाद से पूरी तरह मेल बिठाया गया है। यही वह काम है, जिसके लिए एआई की मदद ली गई है। दोनों ही पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएं, तो आपको ऐसे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे।

इनके साथ ही ऐसे वीडियो भी बनाए गए हैं, जो पूरी तरह से एआई से तैयार किए गए हैं। इसकी शुरुआत आप ने की। पहले एक वीडियो आया, जिसमें बाबा साहेब आंबेडकर अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर एक वीडियो आया, जिसमें केजरीवाल एक बच्चे की उंगली पकड़कर उसे एक आलीशान स्कूल में ले जा रहे हैं। एक वीडियो में वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने बैठे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वह बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

चुनाव आयोग ने अब कहा है कि ऐसी सामग्री पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि इसे एआई से तैयार किया गया है। कुछ सप्ताह पहले भाजपा ने एआई से तैयार एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी एक-दूसरे के सामने बैठे आपस में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने पुजारी-ग्रंथी सम्मान निधि के नाम पर दिल्लीवासियों को किस तरह ठगा। पेशेवर क्वालिटी का यह वीडियो पहली नजर में फर्जी नहीं लगता। हालांकि, भाजपा ने एक सतर्कता जरूर बरती कि उसने वीडियो के निचले हिस्से में स्पूफ यानी मजाक या व्यंग्य लिख दिया था। अब चुनाव आयोग का कहना है, यह बिल्कुल साफ-साफ लिखा जाना चाहिए।

कई बार 'साफ-साफ' का अर्थ भी बहुत साफ नहीं होता। आयोग के दिशा-निर्देश जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एक आलीशान महल में टहल रहे हैं और विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं। इस वीडियो में नीचे बहुत बारीक अक्षरों में आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए लिखा गया है- 'एआई जेनरेटेड वीडियो', यानी यह वीडियो एआई द्वारा तैयार किया गया है। इस वीडियो की चमक-दमक और तेज संगीत के बीच धूसर दिखने वाले ये अक्षर आपसे नजरअंदाज रह जाएं, इसकी वहां पूरी व्यवस्था है।

यही वजह है कि चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए हैं, वे नाकाफी लगते हैं। क्या इसे उस तरह से नहीं किया जा सकता, जैसे सिगरेट की डिब्बी पर स्पष्ट चेतावनी लिखी होती है। साफ-साफ शब्दों में यह क्यों नहीं लिखा जा सकता कि 'यह वीडियो वास्तविक नहीं है, इसे कृत्रिम बुद्धि या एआई से तैयार किया गया है।' इस सूचना के अक्षरों का आकार क्या हो, इसके बारे में भी नियम बनाना जरूरी है। एक और जरूरी बात। वीडियो जिस भाषा में है, सूचना भी उसी भाषा में लिखी जानी चाहिए। उनके सामने जो चुनाव प्रचार सामग्री परोसी जा रही है, वह असली है या नहीं, यह मतदाताओं को जानने का अधिकार मिलना ही चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अनेक नामवर और गुमनाम नायकों को पद्म सम्मान

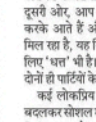

वहां स्कैन करें

विवेक शुक्ला | वरिष्ठ पत्रकार

जापान के उद्यमी ओसामु सुजुकी ने हिन्दुस्तानियों को करीब चार दशक पहले अपनी कार चलाने का सपना दिखाया था। उन्होंने सुजुकी मोटर्स और भारत सरकार के उपक्रम मारुति उद्योग के साथ मिलकर मारुति-800 कार लांच की। सुजुकी ने भारत में ऑटो क्रांति की नींव रखी थी। उन्हें देश के 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। याद रहे कि आर्थिक उदारीकरण की बयार बहने से कई साल पहले मारुति-800 लांच हो गई थी।

लोक गायिका शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने से करोड़ों भोजपुरीभाषी प्रसन्न होंगे। काश! उन्हें जीते जी यह सम्मान मिल पाता। उधर, सौ वर्ससे देख चुकी गोवा की आजादी के लिए लड़ी लिबिया लोबो सरदेसाई को पद्मश्री सम्मान मिला है। उन्होंने 1955 में पुर्तगाली शासन के खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए भूमिगत रेडियो स्टेशन 'वोज दा लिबर्डे' (आजादी की आवाज) की स्थापना की थी। उनके अटूट समर्पण को सरकार ने देर से पहचाना। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी विरासत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

इस बार पद्म सम्मान कई उन विभूतियों को भी दिए गए, जो मीडिया की सुर्खियों से दूर रहकर अपना काम कर रहे है। अब गोकुल चंद्र डे को ही लें। पश्चिम बंगाल के 57 वर्षीय ढाक वादक गोकुल चंद्र डे को पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्र ढाक वादन में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करके लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने के उनके प्रयासों के लिए पहचाना गया और पद्मश्री से नवाजा गया। डे ने पारंपरिक संस्करण की तुलना में 1.5 किलोग्राम कम वजन वाला हल्का ढाक वाद्य यंत्र बनाकर नवाचार भी किया है।

इस बार पद्म सम्मान कई उन विभूतियों को भी दिए जा रहे हैं, जो मीडिया की सुर्खियों से दूर रहकर भी अपना काम कर गए या कर रहे हैं।

इसी क्रम में सम्मानित हो रही विभूतियों में महिला सशक्तिकरण की पैरोकार अमेरिकी मूल की 82 वर्षीय सैली होलकर भी हैं। उन्होंने खत्म हो रहे माहेश्वरी शिल्प को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पारंपरिक बुनाई तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महेश्वर, मध्य प्रदेश में एक हथकरघा स्कूल की स्थापना की। पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के उनके अथक प्रयासों ने उन्हें पद्मश्री दिलाया है। आज ऐसे विभूतियों की कहानियां कई लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रही हैं।

पद्मश्री सम्मान 2025 उन व्यक्तियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने समाज पर महत्वपूर्ण असर डाला है। पद्म सम्मानों की घोषणा होने के बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डी स्कूल) के डायरेक्टर और प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर राम सिंह कुछ भावुक होकर कहने लगे कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच होते, तो उन्हें गर्व होता कि जिस डी स्कूल में वह शिक्षक रहे, वहां के दो पूर्व शिक्षकों क्रमशः प्रो के एल कृष्णा, प्रो वी आर पंचमुखी और एक छात्र बिबेक देबरॉय को पद्मश्री के लिए चुना गया है। देबरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके गहन ज्ञान और विश्लेषण के लिए जाना जाता था। इसके अलावा वह महाभारत के भी प्रकांड विद्वान थे। उनका पिछले साल नवंबर में ही निधन हुआ है।

इस वर्ष के विजेताओं में अमेरिका में बसे सबसे खासमखास भारतीयों में से एक उद्यमी विनोद धाम भी हैं। उन्हें पेंटियम चिप का जनक माना जाता है। पेंटियम प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अमेरिका में भारत के हितों के लिए काम करते हैं।

पद्मभूषण से नवाजी गईं साध्वी ऋतंभरा के नाम पर कुछ आपत्ति हो सकती है, पर यह भी सच है कि साध्वी ने कई सामाजिक कार्य भी किए हैं। उन्होंने वात्सल्य ग्राम संगठन की स्थापना की है, जो अनाथ बच्चों और निराश्रित महिलाओं की देखभाल करता है। बहरहाल, सौ वर्षीय साहित्यकार रामदरश मिश्र, गजल गायक पंकज उदास, फिल्मकार शेखर कपूर और अनंत नाग, भारतीय हॉकी की दीवार माने गए गोलकीपर पी आर श्रीजेश और जुझारू क्रिकेटर आर अश्विन वगैरह को भी पद्म सम्मान मिला है। ये सब देश के नायक हैं, जिनकी चर्चा खूब हो रही है। इन नायकों व उनके परिजन का जमघट दिल्ली में मार्च या अप्रैल में लगेगा, जब इन्हें सम्मानित किया जाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अड़सठ तीरथ हैं घट भीतर

कुम्भ मेले के माहौल में जैसे पूरा समाज जागृत हो गया है। कई तलों पर लोग सोचने लगे हैं कि यह क्या चीज है? मेला जिस उमंग लगा है, उसको तीर्थराज कहते हैं। तीर्थ शब्द बड़ा पुराना है। यह भारतीय अध्यात्म की खोज है। *पद्म पुराण*, *देवी भागवत* और वेदों में भी यह पाया जाता है। लिखा गया है, यह नदी के किनारे या पर्वत पर हो और जल शुद्ध हो, ताकि लोग उसमें स्नान कर सकें। आज के वैज्ञानिक जगत में यह संदेह उठता है कि क्या तीर्थ के जल में स्नान करने मात्र से पाप धुल जाते हैं? आप किसी की हत्या करें और नदी में डुबकी मार लें, तो क्या आपका अपराध धुल जाएगा? नहीं! पाप को धोना इतना आसान नहीं होता और भारतीय ऋषि इतने नासमझ नहीं थे।

पुराणों में तीर्थ के बारे में जो कहा गया है, उस पर ध्यान दें। *पद्म पुराण* कहता है, 'जिसके अंग, मन, ज्ञान, तप और यज्ञ उसके अपने वश में हैं, जो शरीर से पवित्र रहता है, अहंकार से रहित है, संतुष्ट है और कभी भी दान स्वीकार नहीं करता, उसे तीर्थों में जाने से मोक्ष मिलता है।'

देवी भागवत में एक बार ऋषि च्यवन ने प्रह्लाद से कहा : 'केवल वे लोग, जो हृदय से शुद्ध हैं, उन्हें पवित्र स्थानों पर जाने का लाभ मिलता है। गंगा के तट गांवों और नगरों से भरे हुए हैं। कई प्रकार के लोग वहां बसते हैं, वे पवित्र नदी में स्नान करते हैं और पवित्र जल पीते भी हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि उनका मन और हृदय स्वच्छ नहीं है।'

मगर समय की लंबी धारा में सत्य पर धूल चढ़ जाती है और उसमें मूल आशय खो जाता है। ओशो ने हर प्रक्रिया को धूल से उठाकर, चमकाकर उसका वैज्ञानिक कारण बताया है। वह कहते हैं, तीर्थों को बनाने का प्रयोजन यह था कि हम इस तरह की ऊर्जा से भरे हुए स्थल पैदा कर लें, जहां से कोई भी व्यक्ति सुगमता से अंतर्यात्रा कर सके। तीर्थ वैसी जगह थी, जहां से चेतना की एक धारा अपने आप प्रवाहित हो रही है, जिसको प्रवाहित करने के लिए सदियों ने मेहनत की है। आप सिर्फ उस धारा में खड़े हो जाएं, तो आपकी चेतना का पाल तन जाए और आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाएं। जितनी मेहनत आपको अकेले में करनी पड़े, उससे बहुत कम मेहनत में यात्रा संभव हो सकती है। ध्यान के क्षण में आसपास नकारात्मक तरंगें हों, तो ध्यान महंगा भी पड़ सकता है, इसीलिए तीर्थ का ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

ओशो कहते हैं, तीर्थों को बनाने का प्रयोजन यह था कि हम इस तरह की ऊर्जा से भरे हुए स्थल पैदा कर लें, जहां से कोई भी व्यक्ति सुगमता से अंतर्यात्रा कर सके।

वस्तुतः असली तीर्थ तो भीतर है। कबीर साहब कहते हैं, *अड़सठ तीरथ हैं घट भीतर, वाही में मन मल धोओ जी!* यदि बाह्य तीर्थ आपको आंतरिक तीर्थ के लिए तैयार कर दे, तो तीर्थयात्रा सफल हुई।

अमृत साधना

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 26 जनवरी, 1950

गणराज्य का श्रीगणेश

भारतीय गणराज्य का विधिपूर्वक श्रीगणेश हो गया। इसकी मुख्य रस्म राजधानी के सरकारी भवन के दरबार हाल में सम्पन्न हुई। भारत के अन्तिम गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने घोषित किया कि भारतीय विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत विधान के अनुसार भारत २६ जनवरी से सर्वप्रभुता सम्पन्न लोकतंत्री गणराज्य बन रहा है और भारतीय संघ और उसके अंगभूत राज्य इस विधान के अनुसार सरकार और शासन के समस्त अधिकारों का उपभोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे। भारतीय गणराज्य के निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने इसी अवसर पर अपने पद की शपथ ली और एक संक्षिप्त किन्तु प्रेरणास्पद भाषण दिया। यह सन्तोष का विषय है कि उन्होंने शपथ राष्ट्रभाषा हिन्दी में ली और अपना पहला भाषण भी हिन्दी में दिया। इससे यह आशा की जा सकती है कि राजकीय कार्योबार में राष्ट्रभाषा का व्यवहार उत्तरोत्तर बढ़ता जायेगा और निश्चित अवधि के पूर्व ही वह पूर्णतया राजभाषा के पद पर आसीन हो जायेगी।

भारत ने अपनी पराधीनता के अन्तिम चिन्हों को भी गणराज्य की स्थापना द्वारा समाप्त कर दिया है। व्यवहार रूप में भारत १५ अगस्त, १९४७ को ही अपने भाग्य का स्वयं विधाता बन गया था। किन्तु कानूनी रूप में यह अब पूर्ण स्वतन्त्र हुआ है। ब्रिटेन के राजा की सर्वोपरि सत्ता अब पूरी तरह खत्म हो गई। ब्रिटेन और भारत के बीच पुराने सम्बन्धों का अन्त हुआ, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भविष्य में उनके बीच किसी प्रकार का संबंध ही नहीं रहेगा। भारत गणराज्य होने के बावजूद राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहेगा, किन्तु यह व्यवस्था पारस्परिक लाभ की दृष्टि से की गई है...। देश की इस अबाध स्वतंत्रता पर कौन ऐसा अभागा भारतीय होगा, जिसने प्रसन्नता का अनुभव नहीं किया होगा? देशव्यापी समारोहों में जन-साधारण की यह प्रसन्नता झलक उठी थी। ... राजधानी में तो ऐसा प्रतीत हुआ, मानो सन् ४७ का १५ अगस्त पुनः लौट आया हो। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति के दर्शन करने के लिए न केवल राजधानी के निवासी, बल्कि दूर-दूर के लोग उमड़ आये थे और जिस मार्ग से उनकी राजकीय सवारी निकलने वाली थी, उसकी दोनों ओर असंख्य नर-नारी, बाल और वृद्ध घण्टों पहले जमा हो गये थे।

पुरानी पीढ़ी आज के मुकाबले कहीं बेहतर

मानव सभ्यता की विकास-यात्रा में अब हम उन सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य के साधनों से संपन्न हो रहे हैं, जिनको पाना एड़ी-चोटी का जोर लगाने के बाद भी दुष्कर था। जैसे, मोबाइल फोन तीन दशक पहले अधिसंख्य लोगों की कल्पना से परे था। जिस वर्ग के लोग जैसे-वैसे साइकिल और घर के एक कमरे में पंखा जुटा पाते थे, आज गर्मियों में उन्हीं की नव-पीढ़ी को एसी के बगैर नींद नहीं आती। स्नानघरों में कीमती सैंपू और प्रसाधन सामग्रियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी हाई-फाई है, अनेक काम झट से करना-कराना जानती है। फिर भी, जीवन में जो-जो ठीक रहने के लिए अहम है, उसका विलोप हो रहा है; नई पीढ़ी को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। पुरानी पीढ़ी की तुलना में नई पीढ़ी जिस दिशा की ओर अग्रसर है, वहां से वापसी दुष्कर है। ये अच्छे संकेत नहीं हैं।

कहावत है, उड़ना अच्छी बात है। किंतु नई पीढ़ी की फितरत है, इतनी ऊंचाई पर उड़ते रहा जाए कि जमीन भी न दिखे और फिर एलान किया जाए कि आसमां नीचे और मैं ऊपर! उसके दिमाग में यह कौंधता ही नहीं कि नीचे देखकर नहीं चलेंगे, तो ठोकरें लगेंगी। नई पीढ़ी में खासी तादाद उनकी है, जो आकार, वजन और पगार में पिता की टक्कर के, या यूं कहें कि उनसे इक्कीस ही हैं। उन्हें खुशफहमी हो जाती है और आज जिस मुकाम पर वे पहुंचे हैं, उसका श्रेय उनकी अपनी प्रतिभा, लगन व बुद्धि को जाता है। उनके मुताबिक, उनकी शिक्षा और परवरिश में तंगहाली के चलते माता-पिता ने जो कष्ट उठाए, स्वयं को भींचा, यह उनका नैतिक दायित्व था। ऐसा करके उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। कुछ तो तंज कसते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? यह सोच उनकी दुर्गति का सबब बनने लगती है। इसी तरह, अपनी परंपरा और संस्कारों की अनदेखी, बल्कि इनसे दुराव नई पीढ़ी को उस संबल से वंचित रखता है, जो अपनी अस्मिता से जुड़ाव से आजीवन मिलता रहता है।

उपयोग में आगे भी काम आ सकने वाले उत्पादों को खारिज न करने की पुरानी पीढ़ी की किफायत की आदत, जहां उन्हें संतुष्टि देती है, वहीं नई पीढ़ी को यह संदेश भी देती है कि बर्बादी पर रोक पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। संबंधों को निभाना-रखना उच्च मानवीय गुण है, यह किसी तप से कम नहीं है। पुरानी पीढ़ी यह भली-भांति समझती है। शून्य या मामूली प्रयास से, कम समय में काफी सारा चाहने की इच्छा रखने वाली और डिजिटली सोच वाली नई पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाजारी संस्कृति की गिरफ्त में है। वह आत्मीय संबंधों की गरिमा और गमंडित का लुत्फ ले, तो भला कैसे?

हरीश बड़थ्वाल, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
पीढ़ियों में खींचतान

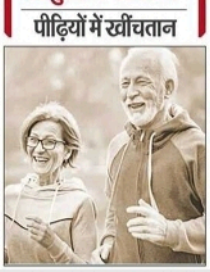

समय के अनुसार बदलने वाला ही टिकेगा

बुजुर्गों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हमारी पीढ़ी बेहतर है और आज की पीढ़ी कमजोर या बेकार। जबकि, यह वैज्ञानिक रूप से भी असंगत बात है। अगर क्रमशः विकास और बेहतर संघर्षशीलता न हो, तो वह प्रजाति ही समाप्त हो जाए। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी पर वैल्यू एडीशन है, जैसे फोन या उपकरणों के नए मॉडल आते हैं। यूरोप में हुए एक सर्वे के अनुसार, युवाओं में प्रति व्यक्ति सिगरेट और शराब की दर पिछली पीढ़ी के मुकाबले कम है। स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति चेतना बेहतर है। वे भले किताबों के बीच डूबे कम दिखें, पर उनका सर्वांगीण विकास और ज्ञान का विस्तार बेहतर हो रहा है। आज का दस वर्ष का बालक आज से चार दशक पहले के दस वर्ष के बालक से अधिक ज्ञान रखता है, वह भी बिना विद्यालयों में सीखे। ये विवाद भी चलते रहते हैं कि बच्चों को डिजिटल दुनिया से दूर रखना चाहिए। मगर सनडांस फिल्मोत्सव में पुरस्कृत एक वृत्तचित्र है, जो यहीं मेरे नगर के एक परिवार पर है। वे लोग अपने बच्चों सहित पूरे परिवार को पास के एक जंगल में रखते रहे। उनको सभी गैजेट से दूर रखा। उन्हें घर में ही शिक्षा देते रहे, प्रकृति के साथ जीना सिखाते रहे। ऐसा करते हुए उनकी मां इसकी ब्लॉगिंग कर रही थी, जो खासा लोकप्रिय हो रहा था। डिजिटल दुनिया में यह स्टॉकिंग उनके जीवन का विरोधाभास था। एक दिन उनको कैंसर हो गया और वह चल बसीं। अब बिन मां के बच्चे, जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी आइपैड या मोबाइल नहीं छूआ, उनकी क्या दशा होती है, वह उस फिल्म में है। हम चाहें, तो अपने मन-मस्तिष्क में उनकी मुश्किलों की कल्पना कर सकते हैं। जाहिर है, पिछली पीढ़ी को आज के समय में रहना है, तो उसे नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाकर चलना ही होगा।

प्रवीण झा, टिप्पणीकार

घर में भी देखिए

समय के साथ जो चलता है, समय भी उसी का साथ देता है। यह ठीक है कि पुरानी पीढ़ी ने एक बुनियाद तैयार की है, लेकिन महज इसी के आधार पर यह दावा करना गलत होगा कि नई पीढ़ी से बेहतर पुरानी पीढ़ी थी। चलिए, मान लेते हैं कि पुरानी पीढ़ी बेहतर थी, तो क्या वह नई पीढ़ी की तरह 'स्मार्ट' थी? नए-नए उपकरणों को आत्मसात करने में इतनी ही उत्सुक थी? नहीं, वह पीढ़ी भले ही अपने दौर में अच्छी मानी जाए, लेकिन आज की तुलना करने पर वह कमतर ही साबित होगी। यकीन न हो, तो अपने घर में ही देख लीजिए। घर के बड़े-बुजुर्ग जहां नई तकनीक को अपनाने में सुस्त होंगे, वहीं आपके बच्चे तकनीक के मामले में आप पर बीस ही साबित होंगे।

कुणाल, टिप्पणीकार

निर्मला सीतारमण | केंद्रीय वित्त मंत्री

भारत पहले रक्षा सामग्रियों के सबसे बड़े आयातकों में से एक था, मगर पिछले कुछ वर्षों में देश के भीतर रक्षा उत्पादन पर जिस तरह जोर दिया गया, वह हमारे लिए गर्व की बात है। इसने भारत को रक्षा सामग्रियों का शुद्ध निर्यातक बना दिया है।

कल्पमेधा

साधनों द्वारा नहीं, बल्कि नैतिकता के बल द्वारा ही मनुष्यों और उनके कर्मों पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

– कार्लाइल

सहमति के बजाय

संसदीय समितियों से अपेक्षा की जाती है कि जिन विधेयकों पर सदन में सहमति न बन पाए, उन पर कानूनी दृष्टि से विचार-विमर्श कर सुझाव पेश करें। कई बार कुछ विधेयकों या कानूनों में संशोधनों पर विपक्ष आपत्ति उठाता और उन्हें संयुक्त संसदीय समिति में विचार की मांग करता है। ऐसा इसीलिए होता है कि संसदीय समितियों की निष्पक्षता पर सबको भरोसा होता है। संवैधानिक भावना यह है कि संसदीय समितियों को सत्तापक्ष के दबदबे से दूर रखा जाए, ताकि विचार के लिए आए विषयों पर तार्किक और निष्पक्ष ढंग से विचार हो सके। मगर पिछले कुछ समय से जिस तरह संयुक्त संसदीय समितियों में हंगामे देखे गए हैं, उससे उनकी प्रासंगिकता पर ही सवाल उठने लगे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति में एक बार फिर हंगामा हुआ और उसके अध्यक्ष ने दस विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि अध्यक्ष सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और वे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं देना चाहते। इसकी लिखित शिकायत भी उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को भेजी है।

दरअसल, सरकार ने वक्फ कानूनों में संशोधन का विधेयक तैयार किया है। उसके मुताबिक वक्फ के फैसलों को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। फिर, कोई भी ऐसी जमीन, जिसे दान में नहीं दिया गया है और वहां मस्जिद या अन्य इबादतगाह बनाई गई है, तो उसे अवैध कब्जा माना जाएगा। दरअसल, इस संशोधन को लेकर मुसलिम धर्मगुरुओं, नेताओं और विपक्ष ने आशंका जाहिर की थी कि सरकार नए संशोधन कानून के जरिए वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। इसलिए सदन में बिना बहस के ही सरकार ने उस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष विचार के लिए भेज दिया था। समिति को अपने सुझाव बजट सत्र में पेश करना है। मगर जिस तरह समिति की बैठकें हंगामे की भेंट चढ़ती रही हैं, उससे नहीं लगता कि कोई सर्वमान्य फैसला हो पाएगा। इस संशोधन विधेयक के खिलाफ कई मुसलिम संगठन भी संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष विरोध जता चुके हैं। किसी संयुक्त संसदीय समिति में जब भी अध्यक्ष सत्तापक्ष का होता है, तो ऐसे विवाद की गुंजाइश बनी ही रहती है। वक्फ कानून वैसे भी संवेदनशील विषय है, इसलिए अगर इस पर राजनीतिक नफे-नुकसान के मद्देनजर विचार रखे जाएंगे, तो उनके निष्पक्ष रहने का दावा नहीं किया जा सकता।

सरकार के पिछले कार्यकाल के वक्त भी संसदीय समितियों के गठन और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर खासा विवाद उठा था। जिन समितियों के अध्यक्ष पद पर सत्तापक्ष के किसी सांसद को नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए, उन पर भी सत्तापक्ष काबिज हो गया था। तब भी संसदीय समितियों की प्रासंगिकता पर सावल उठे थे। संयुक्त संसदीय समिति में हर दल और पक्ष के लोग रखे ही इसलिए जाते हैं, कि वहां किसी विवादित विषय पर हर कोण से विचार-विमर्श हो सके और एक सर्वमान्य, सर्वहितकारी कानून बनाया जा सके। मगर शायद यह मकसद अब गौण मान लिया गया है और इन समितियों को भी राजनीतिक रस्साकशी का मंच बना दिया गया है। इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष और विपक्षी दलों को भी आपसी सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना संयुक्त संसदीय समितियां एक दिखावा भर बन कर रह जाएंगी।

इंसाफ का कठघरा

वर्ष 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों की याद आज भी दिल दहला जाती है। तब जो हुआ था, उसे दुनिया का सबसे बर्बर आतंकी हमला माना जा सकता है। उसके बाद उसमें शामिल आतंकवादियों को पकड़ने से लेकर सजा तक पहुंचाने को लेकर समूचे सरकारी तंत्र ने जितना संभव हो सका, किया। मगर अब भी कुछ ऐसे आतंकी देश के कानूनी दायरे से बाहर हैं, जो किसी तरह अन्य देशों में भाग गए, उन्हें वापस लाने के लिए वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा था। भारत हर स्तर पर उन अपराधियों को सजा दिलाने की कोशिश करता रहा है। मुंबई हमले के एक अभियुक्त तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने की मांग उनमें से एक थी। तहव्वुर राणा इस मांग का विरोध कर रहा था और उसने अमेरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। मगर अब राणा की भारत को प्रत्यर्पित करने संबंधी पुनर्विचार याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस तरह राणा को भारत लाकर उस पर कानूनी प्रक्रिया चलाने का रास्ता साफ हो गया है।

मुंबई हमले में जिनके परिजन मारे गए थे, उनकी पीड़ा जगजाहिर है। अजमल कसाब को उसके किए की सजा मिल चुकी है। हमले का एक आरोपी पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा अभी अमेरिका की जेल में है। दरअसल, राणा को अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमले में भागीदारी करने और इसके बाद डेनमार्क में आतंकी हमले की योजना बनाने का दोषी पाया गया था। लेकिन मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के संदर्भ में उसकी भूमिका के मद्देनजर भारत अपनी अदालत में उस पर मामला चलाना चाहता है। यह भी सच है कि हमले के बाद इतना लंबे वक्त तक अगर उसे भारत लाकर मुकदमा चलाना संभव नहीं हो पाया, तो उसकी वजह यही होगी कि समय पर कूटनीतिक पहल नहीं हुई। अब अगर उसके भारत में प्रत्यर्पण की स्थिति बनी है तो सरकार को कोई अन्य और नई अड़चन खड़ी होने से पहले उसे भारत लाकर कानून के कठघरे में खड़ा करना चाहिए और शीघ्र इंसाफ सुनिश्चित करना चाहिए।

तरक्की के कोलाहल में सुस्त रफ्तार

असली बात तो यह है कि चाहे विकास दर सबसे ऊंची रहे, आम आदमी का हाल क्या है? भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं तो यह दुनिया को छोड़िए, एशिया के पिछड़े हुए देशों के समकक्ष आ जाती है।

सुरेश सेठ

कहा जा रहा है कि हम अगले वर्ष यानी 2026 में दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बन जाएंगे और उससे अगले वर्ष 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। 'फिक्की' का कहना है कि भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटकर 6.4 फीसद होगा। मगर प्रमुख अर्थशास्त्रियों का निष्कर्ष है कि 2025 में वृद्धि तेज बनी रहेगी। दुनिया में सबसे तेजी से भारत बढ़ेगा और इसके दम पर दक्षिण एशिया की जीडीपी भी बढ़ जाएगी। चाहे विश्व आर्थिक मंच ने भारत के बुनियादी ढांचे में अपेक्षित निवेश न होने की ओर इंगित किया था, लेकिन चूंकि इन अर्थशास्त्रियों ने चीन में भी अर्थव्यवस्था के धीमी होने का अनुमान लगाया, इसलिए उसकी तुलना में अपने आप को आगे पाकर हम एक ठंडी दिलासा ले सकते हैं। ठंडी दिलासा इसलिए कि असली बात तो यह है कि चाहे विकास दर सबसे ऊंची रहे, आम आदमी का हाल क्या है? भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं तो यह दुनिया को छोड़िए, एशिया के पिछड़े हुए देशों के समकक्ष आ जाती है। अपनी तारीफ में चाहे आप कह लें कि दुनिया भर में अमेरिका के बाद सबसे कुशल भारतीय पेशेवर हैं, भारतीय युवा एआइ, डिजिटल और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में सबसे कुशल हैं। मगर याद रखिए कि तीसरी आर्थिक ताकत बनने का सपना देखने वाला भारत दुनिया में 'ओवरआल रैंकिंग' में पच्चीसवां रहा है। यह रैंकिंग 'स्किल फिट एकेडेमिक रेडिनेस फ्यूचर आफ वर्क' और आर्थिक बदलाव पर आधारित है। कहने की बात नहीं कि यहां हम तैयारी और परिवर्तनशीलता के अभाव में अभी तक फिसड्डी हैं।

भारत अपनी नई उपलब्धियों की घोषणा करते थक नहीं रहा। कहा जा रहा है कि इस साल भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया, जब उसने दो उपग्रहों को जोड़ दिया। ऐसा करने वाला यह दुनिया का चौथा देश बन गया है। यही नहीं, धरती पर भारत की डिजिटल ताकत की वृद्धि का अंत नहीं। नया आंकड़ा आया है कि इस साल हमारे देश के इंटरनेट उपयोग कर्ताओं की संख्या नब्बे करोड़ के पार पहुंच जाएगी। 2024 में यह 88.6 करोड़ थी। ग्रामीण भारत भी इंटरनेट के इस्तेमाल में आगे बढ़ रहा है। कुल आबादी में इसकी हिस्सेदारी 55 फीसद हो गई है। दूसरी ओर, तरक्की का यह आलम है कि सोना दो महीने बाद 81 हजार रुपए से पार चला गया। चांदी 94 हजार रुपए प्रति किलो पर पहुंची। नव धनकुबेरों ने बहुत महंगे फ्लैटों और बड़ी कारों की बिक्री शिखर पर पहुंचा दी। चाहे इस धूम धड़ाके में उन गरीबों की सुध लेने की उम्मीद पहली फरवरी को पेश होने वाले बजट पर छोड़ दी गई है, जहां उन्हें कुछ और रियायतें देकर शायद उनका जीवन सहज किया जाए।

आम आदमी की उम्मीद तो यही है कि भूख से मरने न देने की गारंटी तो दे दी, अब शिक्षा के अनुसार रोजगार देने की गारंटी भी दे दो। पर उसके लिए नई उद्यम नीति बनाने की जरूरत है। निवेशकों का उत्साह गिरने न देने की जरूरत है। मगर हमारे शेयर बाजार के सूचकांक क्यों

धराशायी होते नजर आ रहे हैं? क्यों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फेडरल दरों से आकर्षित होकर भगोड़ा हो रहा है? और क्यों देश की स्थायी तरक्की में ये आंकड़े परेशान कर रहे हैं कि पूरी कमाई पर्यटन, होटल और सेवा क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमने लगी है। खेतिहर बेहतर आर्थिक स्थिति में नहीं

> **हम भारत को आयात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन नए आंकड़े कहते हैं कि हमारी आयात जरूरतें कम नहीं हुईं। आत्मनिर्भरता के नारों के बावजूद हम आत्मनिर्भर नहीं हुए, लेकिन हमारा निर्यात अवश्य एक फीसद कम हो गया। अमेरिका और चीन पर हमारी आयात निर्भरता उसी तरह खड़ी है। अगर भारत डालर पर निर्भरता को कम करके किसी वैकल्पिक मुद्रा से विनिमय का सपना देखता है, तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप उसे बढ़े हुए शुल्क का भय दिखाने लगते हैं। इस सब तरक्की के नारों के बावजूद देश की आबादी का बड़ा हिस्सा अपने आप को तरक्की के हाशिये से बाहर क्यों पाता है?**

आया। विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती है। इसके साथ शेयर सूचकांक लगातार गिरावट दिखा रहे हैं। फिक्की से लेकर अन्य अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थान तो कहते हैं कि गिरावट के बावजूद भारत गति पकड़ लेगा और हम अपनी आर्थिक वृद्धि का स्तर बनाए रखेंगे।

आर्थिक विकास दर में हम बाहुबली देशों से आगे रहेंगे। मगर प्रश्न है कि चीन तो अपनी आर्थिक नीतियों की रुग्णावस्था के कारण पिछड़ने लगा, पर 'चीन प्लस' का यह अतिरिक्त निवेश भारत की ओर क्यों नहीं आया? क्यों वैश्विक दक्षिण के दूसरे देशों की ओर मुड़ गया? क्या इसका कारण यह नहीं है कि हम दफ्तरशाही और लालफीताशाही की नाक में नकेल नहीं दे सके? भ्रष्टाचार को शून्य स्तर पर पहुंचाने की घोषणाओं के बावजूद हम भ्रष्टाचार के सूचकांक में फिर उसी पायदान पर अटके हैं। वैसे, इस नए युग में भारत में गर्व करने योग्य बहुत-सी बातें हैं। पहली बात तो यही है कि भारत ने देश में एक युवा वर्ष लाने का वादा किया है। इस साल प्रधानमंत्री के पहले वक्तव्य और पहले संदेश को किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के नाम कर दिया गया है। कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की कमाई के बीच एक असंतुलन और असंतुष्ट विभाजन का खतरा भी पैदा हो गया है। पंजाब को ही अगर देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा हो गई, लेकिन पंजाब अपने छठवें वेतन आयोग की कमियां ही पूरी नहीं कर पा रहा।

जहां तक समतावाद का संबंध है, केंद्र सरकार ने गरीबों का भला करने का संकल्प इस वर्ष की शुरुआत में लिया है। उसने गरीबी उन्मूलन का संदेश भी दिया है और युवाओं को नए युग के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली में ही 600 करोड़ की नई शैक्षणिक योजनाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है। किसी इलाके में चुनाव घोषित होते हैं, तो वहां नई विकास योजनाओं की घोषणाओं की बाढ़ आ जाती है, लेकिन विरुफारित नेत्रों वाली आम जनता यह पूछती है कि ये परियोजनाएं पूरी कब होंगी? औसत मूल्यांकन यह है कि जितनी परियोजनाओं की घोषणा होती है, उनमें से तीन-चौथाई अपने निर्धारित समय से पिछड़ जाती हैं। इस तरह उनकी लागत और बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई लागत अंततः बजट घाटे को बढ़ाती, रुपए का विनिमय मूल्य गिराती है और महंगे आयात देश में मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? नए युग की घोषणा करने से पहले यह भी सोच लिया जाए।

एक और दिशा में चिंतन कर लें। इस युग में हम भारत को आयात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन नए आंकड़े कहते हैं कि हमारी आयात जरूरतें कम नहीं हुईं। आत्मनिर्भरता के नारों के बावजूद हम आत्मनिर्भर नहीं हुए, लेकिन हमारा निर्यात अवश्य एक फीसद कम हो गया। अमेरिका और चीन पर हमारी आयात निर्भरता उसी तरह खड़ी है। अगर भारत डालर पर निर्भरता को कम करके किसी वैकल्पिक मुद्रा से विनिमय का सपना देखता है, तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप उसे बढ़े हुए शुल्क का भय दिखाने लगते हैं। इस सब तरक्की के नारों के बावजूद देश की आबादी का बड़ा हिस्सा अपने आप को तरक्की के हाशिये से बाहर क्यों पाता है? इन कल्याणकारी नीतियों में मुफ्तखोरी की झलक मेहनत की आदत के ऊपर क्यों हावी होने लगी है?

भावनाओं का मौन संवाद

सुप्रिया सत्यार्थी

आंसू प्रथम दृष्टया आंखों से बहने वाला पानी दिखता है, लेकिन हम सब समझते हैं कि यह मानव जीवन की सबसे गहरी भावनाओं के अदृश्य पुल हैं। आंसू हमारे मन की कहानी कहते हैं, कभी खुशी से तो कभी गहरे दुख से। यह एक ऐसा माध्यम है, जो शब्दों के अभाव में हमारे भावों को व्यक्त करता है। इसका महत्त्व, प्रकार और इससे जुड़ी मानवीय संवेदनाएं इतनी व्यापक हैं कि इसे केवल एक शारीरिक क्रिया मान लेना अनुचित होगा। मनुष्य के भीतर भावनाओं की व्यापकता और बहुस्तरीय उतार-चढ़ाव के लिहाज से देखें तो आंसू अपने आप में कई प्रकार के होते हैं। हर आंसू अपने बहाव में एक अलग कहानी समेटे होता है। किन्हीं स्थितियों में बहा दिया जाए या बहने दिया जाए, तब ये सिर्फ आंसू हैं, मगर इसके विभिन्न रूपों को समझने की कोशिश इसके नए आयाम खोलती है। दुख के प्रतीक और हर्ष के अतिरेक में बहने वाले आंसुओं के बरक्स सहानुभूति के लिए बहाए गए आंसू सबसे अधिक भ्रमित करने वाले होते हैं। ऐसे आंसू अक्सर भावनाओं का शोषण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस नाम पर बहाए गए आंसुओं में ईमानदारी की कमी होती है और ये दूसरों को अपने प्रति दयालु बनाने का प्रयास करते हैं। इन्हें वास्तविकता का रूप देने के लिए नाटकीयता का भी सहारा लिया जाता है। जैसे कसम खाना, छाती पीटना या खुद को बेचारा दिखाना। ऐसे आंसू संवेदनाओं के कृत्रिम प्रदर्शन हैं, जो सच्चे आंसुओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।

इस वर्ग में दूसरे प्रकार के आंसू ये होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं। इस तरह के आंसू सच्चे तो दिखते हैं, लेकिन इनका केंद्र केवल 'मैं' होता है। ये तब बहते हैं, जब व्यक्ति खुद किसी दुख या पीड़ा का सामना कर रहा हो। इन आंसुओं का संसार केवल व्यक्ति की अपनी समस्याओं तक सीमित होता है। दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी त्रासदी हो, इन आंसुओं का बहाव केवल अपने दर्द तक ही सीमित रहता है। इस तरह के आंसुओं को आत्म-केंद्रित भावनाओं का प्रतीक कहा जा सकता है।

दूसरों के दुख देखकर बहने वाले आंसू मानवीय संवेदनाओं का सबसे सुंदर और कोमल रूप हैं। किसी की परेशानी देखकर कई बार किसी व्यक्ति की आंखों से आंसू अपने आप निकल आते हैं। यह उस हृदय की निशानी हैं, जो न केवल अपने दर्द को महसूस करता है, बल्कि दूसरों के दुख को भी समझने और साझा करने की क्षमता रखता है। ऐसे आंसू इंसान के भीतर की करुणा और प्रेम को प्रकट करते हैं।

सबसे गहरे और रहस्यमय आंसू वे होते हैं, जो आंखों के किसी कोने में छिपे रहते हैं। ऐसे आंसू बिना किसी गवाह के बहते हैं। इन्हें कभी-कभी 'एकांत के आंसू' भी कहा जाता है। ये आंसू व्यक्ति की आत्मा की सच्चाई को बयान करते हैं। इनका कोई श्रोता नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता। ये केवल आंसू बहाने वाले व्यक्ति और उसकी भावनाओं के बीच का मौन संवाद होते हैं। इन आंसुओं का बहना एक प्रकार की आत्म-स्वीकृति और मन की शांति की खोज का संकेत है।

आंसुओं का महत्त्व केवल भावनाओं को व्यक्त करने तक सीमित नहीं है। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। आंसुओं का बहना तनाव को कम करता है और मन को हल्का बनाता है। यह दुख और पीड़ा को व्यक्त करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। आंसुओं से भावनाओं का शुद्धीकरण होता है। ये मन को शुद्ध करते हैं। जब मन दुख से भर जाता है, तो आंसू उसे बाहर निकालने का माध्यम बनते हैं। ये व्यक्ति को अंदर से हल्का और शांत महसूस कराते हैं। सच यह है कि आंसू मानवीय संवेदनाओं के प्रतीक हैं। ये हमें यह समझने का मौका देते हैं कि व्यक्ति का दिल कितना कोमल और संवेदनशील है। ये उस गहरे जुड़ाव को प्रकट करते हैं, जो इंसान को इंसान से जोड़ते हैं। आंसू अक्सर सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत बनाते हैं। जब हम किसी को रोते हुए देखते हैं, तो हमारे भीतर उसकी मदद करने की भावना उत्पन्न होती है। ये मानवीय करुणा और दया का प्रतीक हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **दूसरों के दुख देखकर बहने वाले आंसू मानवीय संवेदनाओं का सबसे सुंदर और कोमल रूप हैं। किसी की परेशानी देखकर कई बार किसी व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आते हैं। यह उस हृदय की निशानी हैं, जो न केवल अपने दर्द को महसूस करता है, बल्कि दूसरों के दुख को भी समझने और साझा करने की क्षमता रखता है।**

आंसू केवल आंखों से बहने वाली बूंदें नहीं हैं। यह जीवन के हर पहलू से जुड़े हैं। खुशी में बहने वाले आंसू यह सिखाते हैं कि जीवन में छोटे-छोटे पलों का जश्न मनाना चाहिए। दुख में बहने वाले आंसू यह याद दिलाते हैं कि जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन इन संघर्षों में छिपा है गहराई और सीखने का अवसर। मौन आंसू यह बताते हैं कि हर भावना को शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक नहीं। कुछ भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है।

आंसू मानव जीवन का एक अद्भुत और अनिवार्य हिस्सा हैं। ये हमारी भावनाओं, संघर्षों और अनुभवों का प्रतिबिंब हैं। इनकी गहराई को समझना आसान नहीं, लेकिन इनका महत्त्व अनमोल है। हर तरह के आंसू एक कहानी कहते हैं। कुछ आंसू छलावा होते हैं, तो कुछ सच्चाई के प्रतीक। कुछ आंसू स्वार्थ से भरे होते हैं, तो कुछ करुणा की दया के। और कुछ आंसू ऐसे होते हैं, जो केवल हमारे सबसे निजी क्षणों के साक्षी होते हैं। हम जब भी आंसुओं को देखें, तो उन्हें केवल पानी की कुछ बूंदें न समझें। यह उन भावनाओं और अनुभवों का प्रतिबिंब हैं, जो इंसान को इंसान बनाते हैं। आंसू हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची संवेदनशीलता और मानवीयता आंखों के इन छोटे-छोटे मोतियों में छिपी होती है।

जोखिम की तकनीक

हाल के दिनों में विभिन्न प्रकार के अपराधियों द्वारा एआइ यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। किसी व्यक्ति की तस्वीर का उपयोग करके उसके संबंध में आपत्तिजनक वीडियो या प्रचार सामग्री तैयार करके उसकी छवि खराब की जाती है। उसके बारे में अनर्गल प्रचार-प्रसार किया जाता है और जब तक जनता या सरकार को इस अपराध की खबर लगती है, तब तक उस व्यक्ति की छवि बरबाद हो चुकी होती है। इस विकृति का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है कि अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार एआइ के जरिए किसी तस्वीर, वीडियो या अन्य सामग्री का उपयोग करे तो उसके स्रोत की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए। आयोग की सलाह एक जरूरी कदम है, फिर भी यह केवल राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अक्सर ये ही इसके जिम्मेदार होते हैं। निर्देश देने के बजाय खुद चुनाव आयोग को भी इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और निर्धारित नियम-कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

सादगी का स्वभाव

सादगी और निश्छलता मनुष्य का गहना है, चरित्र और मानवता है। बदलते समय में लोग ऐसे गुण त्याग रहे हैं और आज के सबसे होशियार, चतुर और आधुनिक बनने की दौड़ में शामिल होने लगे हैं। नतीजा है कि आपसी विश्वास खत्म हो रहा है। निश्छल लोग ढूंढ़े नहीं मिलते हैं। मगर इसके बरक्स दिखावा और पाखंड करने वाले लोग जरूर मिल जाएंगे। आज अर्थोपार्जन से लोगों की सफलता आंकी जाती है, चाहे वह अर्थोपार्जन गलत तरीके से ही क्यों न हो। यह प्रचलन समाज को कितना नीचे धकेल देगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मुंहफट लोग हर चीज के विशेषज्ञ बनते हैं, लेकिन सच्चाई है कि वे नीम हकीम खतरे जान होते हैं। ऐसे लोग खजाने पर डाका डालने वाले होते हैं और किसी काम के नहीं होते हैं। ऐसे में सादगी और निश्छलता रूपी गहने को अपने साथ बनाए रखने की जरूरत है।

– प्रसिद्ध यादव, बाबूघाट, पटना

नए दौर में

भारत का जीवट पहले से ही सिद्ध रहा है, लेकिन अब नए दौर की मुसीबत के समय भी अपनी जरूरतों की पूर्ति करना भारत धीरे-धीरे सीख रहा है। रूस भारत के लिए तेल का बड़ा निर्यातक देश है और उसे रूस से ही सस्ता तेल मिलता है। हाल ही में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंधों के बाद भारत ने अपनी आयात नीति में विविधता लानी शुरू कर दी है। प्रतिबंधों के कारण रूस की तेल आपूर्ति और लेनदेन प्रणाली प्रभावित हो सकती है। इससे सस्ते तेल के अभाव में महंगे आयात से घरेलू तेल कीमतें बढ़नी स्वाभाविक ही होंगी। वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता का माहौल और डालर की मजबूत होती कीमत भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, भारत को वैश्विक हालात और परस्पर रिश्तों के मद्देनजर अपनी नीति तय करनी होगी।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

समय रहते

कोटा जैसे शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले शहर में बच्चों की आत्महत्या की घटनाएं समाज और परिवारों के लिए चेतावनी है। उन जगहों पर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई का अत्यधिक दबाव, असफलता का डर और भावनात्मक संवाद की कमी ऐसी घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। यह छिपा नहीं है कि बच्चों की जिस विषय में अरुचि होती है, अभिभावक उसे पढ़ने के लिए भी बच्चों पर दबाव डालते हैं। इसके अलावा, शिक्षकों की सफलता के साथ असफलता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सिखाना चाहिए। सोशल मीडिया और मोबाइल पर बच्चों की गतिविधियों को संतुलित करने के साथ, खेल, संगीत और योग जैसे शारीरिक और मानसिक विकास के साधनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह समस्या केवल सामूहिक जागरूकता और संवेदनशीलता से सुलझ सकती है।

– हरेंद्र सिंह कलिखा, सीकर, राजस्थान

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 27 जनवरी • 2025
www.rashtriyasahara.com

साहसपूर्ण दूरदर्शिता

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए सरकार के कामों की सराहना की। उन्होंने एक राष्ट्र-एक चुनाव को साहसपूर्ण दूरदर्शिता का प्रयास बताया और औपनिवेशिक मानसिकता को बदलने के प्रयास करते दिखने की चर्चा की। कहा कि एक राष्ट्र-एक चुनाव से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है, नीति निर्धारण से जुड़ी निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है तथा वित्तीय बोझ कम किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने के निर्णय का उल्लेख किया। मुर्मु ने

कहा, स्वतंत्रता के समय देश के कई हिस्से अत्यधिक गरीबी व भुखमरी का सामना कर रहे थे। हमने खुद पर विश्वास बनाए रखा और विकास के लिए परिस्थितियां बनाईं। हाशिए पर जातियों को सहायता प्रदान करने की उन्होंने चर्चा की। प्रयागराज में महाकुंभ को समृद्ध विरासत की प्रभावी अभिव्यक्ति बताया। एक चुनाव का फार्मूला नया नहीं है क्योंकि आजादी के बाद लंबे अर्से तक पूरे देश में एक साथ ही चुनाव कराए गए थे। परंतु मध्यावधि या असाधारण परिस्थितियों में विधायिका के चुनाव कराना असंवैधानिक नहीं रहा। एक साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराना निश्चित ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मगर यह भी सच है कि इससे आर्थिक बोझ कम होगा और विकास कार्यों/सरकारी कामकाज में व्यवधान कम होगा। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अंदेशा जता रहा है कि इससे क्षेत्रीय दलों को झटका लग सकता है। वे इसे सरकार की चतुराई से जोड़, साजिश बता रहे हैं। बावजूद इसके एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार जितनी अडिग है, उसे देखते हुए दिख रहा है कि यह जल्द ही जमीनी स्तर पर कारगर हो सकेगा। रही बात गरीबी-भुखमरी से जूझने या बांचतों को लाभ पहुंचाने की तो इसकी कवायद लंबे अरसे से चालू है। इनका श्रेय सिर्फ मोदी सरकार को नहीं दिया जा सकता। मगर जैसी रिवायत रही है, राष्ट्रपति को सत्ता पक्ष की पीठ ठोंकते ही नजर आना है। सैनिकों, पुलिस व अर्धसैनिक बलों की प्रसंशा के साथ ही उन्होंने न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवाओं व विदेशों में चल रहे मिशनों के सदस्यों की सेवाओं का भी संज्ञान लेकर राष्ट्रीय प्रगति को दोहराया। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में संविधान का सम्मान बढ़ाते हुए प्रति दिन गौरवपूर्ण कदम उठाए जाते रहेंगे।

पुतिन का रुख

मास्को यूक्रेन से युद्ध के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इस तरह की बातचीत पर रोक लगाए हुए हैं। इस बाबत आदेश जारी कर चुके हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच वार्ता कैसे बहाल हो सकती है। बहाल होती है तो यूक्रेन के वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत अवैध होगी। जेलेंस्की के आदेश को देखते हुए

बातचीत शुरू होने की संभावनाओं पर पुतिन ने कहा कि कुछ शुरुआती चर्चा तो हो ही सकती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को फंड मुहैया कराने वाले देशों को भी जेलेंस्की पर दबाव डाल कर पूर्व में दिए जा चुके उनके आदेश को वापस लेने के लिए कहना चाहिए। दरअसल, पुतिन के रुख में बदलाव उन पर चौतरफा दबाव का नतीजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर अमेरिका गंभीर है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने यह बात कही। हालांकि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भी वह कह चुके थे कि पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता करके युद्ध समाप्त करना चाहिए। यह भी कह चुके हैं कि जेलेंस्की भी समझौते के लिए तैयार हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर मंच पर बार-बार दोहरा चुके हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है। दरअसल, विश्व के अनेक देश रूस-यूक्रेन के बीच लंबे समय से छिड़े युद्ध को रोकने के हक में हैं। अन्य देशों ही नहीं बल्कि पुतिन पर अपने अवाम का भी भारी दबाव है। गौरतलब है कि युद्ध में दोनों तरफ के हजारों सैनिक, बच्चे और महिलाएं मारे जा चुके हैं। बमबारी से दोनों देशों की संपत्तियां नष्ट हुई हैं, जिन्हें फिर से बनाने में वर्षों लग जाएंगे। युद्धबंदी नहीं हुई तो घातक हथियारों और परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल भी हो सकता है। जंग इतनी भीषण होगी कि परिणाम की कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। इसलिए जरूरी है कि युद्ध तत्काल रुके। युद्ध पर धन का दुरुपयोग न करके इसे भुखमरी से निजात पाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर खर्चना विश्व के कहीं ज्यादा हित में है। उम्मीद है कि युद्धरत दोनों पक्ष विवेक दिखाएंगे।

सामयिक/नीरज शर्मा 'भरथल'

पैसा सब कुछ नहीं

किसी ने सही कहा है कि पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं, इसका स्पष्ट और सटीक उदाहरण मिला सैफ अली खान पर हुए हमले वाले केस में। सैफ अली खान की पहचान मात्र बॉलीवुड स्टार की ही नहीं है। वो पटौदी राजघराने के नवाब भी हैं, और अथाह संपत्ति के मालिक हैं।

अलीशान महल, बंगले, फ्लैट आदि उनके नाम हैं। करोड़ों रुपया उनके पास है। एक से एक शानदार और महंगी कार उनके फ्लीट में हैं परन्तु जब मुसीबत आई तो कुछ काम न आया, जान बचाने के लिए काम आया तो आम आदमी की सवारी ऑटो रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालक। खबरों के अनुसार 16 जनवरी को आधी रात को एक शख्स, जो चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था, ने चोरी करते समय दबोचे जाने पर सैफ पर चाकू से कई बार किए और वहां से फरार हो गया। इस वारदात में सैफ के शरीर पर 6 जगह चाकू से वार किए गए। लहूलुहान हालत में जख्मी सैफ को अस्पताल ले जाने के समय करोड़ों की महंगी गाड़ियां तो गैराज में कतार लगाए खड़ी थीं पर उन्हें चलाने वाला कोई नहीं था। बच्चे खून से लथपथ अपने पिता को एक ऑटो रिक्शा में बैठा लीलावती हास्पिटल पहुंचे जहां उनका उपचार हुआ। सैफ ने मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ऑटो रिक्शा चालक को मुलाकात के लिए बुला कर उनका धन्यवाद किया। ऑटो चालक का नाम भजन सिंह राणा है। खबरों की मानें तो सैफ ने ऑटो ड्राइवर को शुक्रिया के साथ-साथ पचास हजार रुपये इनाम के तौर पर दिए हैं।

सैफ ने ऑटो चालक की तारीफ भी की और कहा कि आप ऐसे ही सब की मदद करते रहना। सैफ ने हंसते हुए कहा कि उस दिन आपको किराया नहीं दिया गया, लेकिन वह मिल जाएगा। जिंदगी में किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। उनकी मां शर्मिला टैगोर ने भी भजन सिंह का शुक्रिया अदा किया। सैफ की मदद करने के लिए ड्राइवर को एक संस्था ने 11 हजार का इनाम भी दिया है। इसमें कोई शक नहीं रुपया-पैसा इंसान के जीवन में अहमियत रखता है पर यह भी उतना ही सच है कि किसी जान से ज्यादा कीमत पैसे की कभी हो नहीं सकती। यह शाश्वत सत्य है, लेकिन दुनिया है कि पैसे के पीछे पगली हुए जाती है, हालांकि भजन सिंह जैसे लोग बारंबार इसकी क्षणभंगुरता जताते रहते हैं।

'दूषित' पेय पदार्थों का कहर

सामयिक

विनीत नारायण

शीतल पेयों के जरिए हम ऐसे कीटनाशकों को निगल रहे हैं, जिनसे कैंसर, स्नायु और प्रजनन तंत्र को क्षति, जन्मजात शिशुओं में विकृति और ह्म्यून सिस्टम तक में खराबी आ सकती है। कुछ समय पहले हुए एक शोध में सामने आया कि आकर्षक विज्ञापनों के जरिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन शीतल पेयों को आम भारतीयों के गले के नीचे उतार रही हैं, वे सेहत के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं हैं।

वैज्ञानिकों का कहना है कि इन शीतल पेयों के जरिए हम ऐसे कीटनाशकों को निगल रहे हैं, जिनसे कैंसर, स्नायु और प्रजनन तंत्र को क्षति, जन्मजात शिशुओं में विकृति और ह्म्यून सिस्टम तक में खराबी आ सकती है। कुछ समय पहले हुए एक शोध में सामने आया कि आकर्षक विज्ञापनों के जरिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन शीतल पेयों को आम भारतीयों के गले के नीचे उतार रही हैं, वे सेहत के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं हैं

भारतविकता क्या है, यह तो विस्तृत जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट (सीएसई) के अनुसार विदेशी कंपनियां भारत के साथ भेदभाव बरत रही हैं। अमेरिका और अन्य देशों में इनके उत्पादों की गुणवत्ता का बारीकी से ध्यान रखा जाता है, जबकि भारत में ये पैसे बचाने के लिए कीटनाशकों का घोल जनता को पिलाती हैं। पेय पदार्थों में अपशिष्ट पदार्थों की मिलावट विदेशी कंपनियों के शीतल पेयों तक ही सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व बोतलबंद मिनरल वाटर के दूषित होने को लेकर बवाल मचा था। उस समय सीएसई ने देसी-विदेशी विख्यात कंपनियों के बोतलबंद पानी के दिल्ली में 17 और मुंबई में 13 उत्पादों की जांच कर उनमें लिन्डेन, डीडीटी, क्लोरोपाइरीफोस, मेलाथियॉन जैसे कीटनाशक पाए जाने की पुष्टि की थी। इसके बाद सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो की सिफारिश के आधार पर बोतलबंद पानी की शुद्धता बरकरार रखने के लिए खाद्य अपमिश्रण कानून में कुछ फेरबदल कर इन्हें लागू करवा दिया। हालांकि भारत के अधिकांश लोग नगर पालिका या नगर निगम द्वारा आपूर्त जल अथवा नदियों का पानी ही पीते हैं। स्थानीय निकाय पानी को स्वच्छ करने के लिए क्या कदम उठाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। बाहरी जल की तो छोड़िए, बढ़ते प्रदूषण के कारण भूगर्भीय जल भी स्वच्छ नहीं रह गया। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से अनाज, सब्जी और फल तक दूषित हो गए हैं। ज्यादा पैदावार के चक्कर में किसान रासायनिक खादों का बेतरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे भूमि बंजर हो रही है, उपज की गुणवत्ता में कमी आई है, जमीन से उपयोगी तत्व नष्ट हो रहे हैं, आदि-आदि। कभी देश में दूध-दही की नदियां बहा करती थीं, लेकिन आज थोड़े से लाभ के लिए लोग सेहत के लिए नुकसानदेह पदार्थों से नकली दूध तैयार कर रहे हैं। यूरिया, साबुन, तेल जैसी खतरनाक चीजें मिला कर बनने वाले इस दूध में दूध नाम की कोई चीज नहीं होती।

डॉ. वर्गीज कुरियन ने भी भारत में 'ऑपरेशन फ्लड' शुरू करते समय नहीं सोचा होगा कि आम लोगों को दूध मुहैया कराने के लिए वह जिन डेयरियों को खुलवाने की बात कर रहे हैं, उनमें बरती जाने वाली लापरवाही गाय और भैंसों के लिए तो जानलेवा साबित होगी ही, वहां से मिलने वाला दूध भी आम आदमी के लिए मुफीद नहीं रहेगा। भारत में डेयरियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ज्यादा दूध लेने के चक्कर में गायों को हर साल गर्भवती करवा दिया जाता है, क्योंकि बच्चा होने के बाद दस माह तक वह ज्यादा दूध देती है। हर रोज उन्हें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ज्यादा दूध दे सकें परंतु वे इंजेक्शन उनके लिए कितने हानिकारक हैं, यह डेयरी मालिक नहीं जानते। उन्हें पता है तो गंभीर अपराध कर रहे हैं, क्योंकि जानवूझकर किसी को मौत के मुंह में धकेलना कानून में अपराध की श्रेणी में आता है। ये सभी तरीके इन बेजुबान जानवरों के लिए तो खतरनाक हैं ही, इनका दूध पीने वालों के लिए भी कम नुकसानदेह नहीं हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के एक शोध के मुताबिक, गाय के जिस दूध को हम पूर्ण आहार मान पीते चले आ रहे हैं, वह भी कीटनाशकों से भर गया है। उसमें डाईक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन (डीडीटी), हैक्साक्लोरो साइक्लोहैक्सेन (एचसीएच), डेल्ड्रिन, एल्ड्रिन जैसे खतरनाक कीटनाशक मौजूद हैं। रिपोर्ट कहती है कि यदि अल्सर से पीड़ित किसी व्यक्ति को डेयरी का दूध और उसके उत्पाद खाने-पीने को दिए जाएं तो उसे दिल का दौरा पड़ने की आशंका दो से छह गुना बढ़ जाती है। भारतीय खाद्य अपमिश्रण कानून एक किलो में केवल 0.01 मिलीग्राम एलसीएच की अनुमति देता है, जबकि आईसीएमआर की रिपोर्ट में यह 5.7 मिग्रा. प्रति किग्रा. निकला। बैज्ञानिकों को दूध में आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा जैसे खतरनाक खाद्य अपमिश्रण मिले जो इतने खतरनाक हैं, किडनी, दिलोदिमाग तक को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं।

बात गाय और भैंस के दूध तक सीमित नहीं है। खेती के दौरान भारी मात्रा में कीटनाशकों के प्रयोग से बच्चे के लिए अमृत कहा जाने वाला मां का दूध भी शुद्ध नहीं रह गया है। अमेरिका में एक शोध में अमेरिकी औरत के दूध में कीटनाशकों के साथ-साथ सौ से भी ज्यादा औद्योगिक रसायन पाए गए पर नुकसानदेह रसायनों के बावजूद मां का दूध बच्चे के पोषण के लिए बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि प्रति वर्ष करीब दो लाख लोग कीटनाशक खाकर काल के गाल में समा जाते हैं। यह संख्या पिछले दस-बारह सालों में सात गुनी हो गई है। संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 30 लाख लोग इन जहरों की चपेट में आते हैं, और खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे होते हैं। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से पैदा हुई इन स्थितियों को देखते हुए अनेक देशों ने तो इनका प्रयोग लगभग बंद ही कर दिया है, और प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करने लगे हैं। पर भारत अभी पश्चिम से कदमताल कर रहा है। जिस तकनीक को वे उपयोग कर उसके बुरे प्रभावों को देख कर त्याग चुके हैं, भारतीय उनका ही अंधानुकरण कर रहे हैं। वे हमारी पुरातन संस्कृति और सभ्यता के गुणों से परिचित होकर उनका अध्ययन कर गुढ़ रहस्य को समझ कर जीवन में उतारने की कोशिश में लगे हैं, वहीं भारतवासी अपनी समृद्ध संपदा को छोड़ कर पश्चिमी चकाचौंध के दीवाने हुए जा रहे हैं। तकनीक अपनाना, चाहे वह अपने देश की हो या विदेश की, गलत नहीं है पर उसके अच्छे-बुरे प्रभावों को जाने बिना उसका अंधानुकरण करना सही नहीं कहा जा सकता।

(लेख में विचार निजी हैं)

जानकर झटका लगा कि पूर्व ओलंपियनों को 12-24 हजार रुपये की मामूली पेंशन दी जा रही थी। क्रिकेट पर बहुत ज्यादा ध्यान हो तो हम कैसे प्रमुख ओलंपिक देश बन सकते हैं। पूर्व ओलंपियनों के कल्याण की बातत संसद में मेरे सवाल का जवाब वाकई सदमे में डालने वाला था और तमाम सवाल खड़े करता है।

सागरिका घोष, राज्य सभा सांसद
@sagarikaghose

एकजुटता

श्रीराम शर्मा आचार्य

आकर्षक लगने वाली सभी वस्तुएं उपयोगी नहीं होतीं। सर्प, बिच्छू, कांतर, कनखजूरे जैसे प्राणी देखने में सुंदर लगते हैं पर उनके गुणों को देखने पर पता चलता है कि वे समीप आने वाले को कितना त्रास देते हैं? प्रथम पहचान में ही न किसी का मित्र बनना चाहिए और न किसी को बनाना चाहिए। चरित्र के बारे में बारीकी से देखना, समझना और परखना चाहिए। मात्र शालीनता के प्रति आशा रखने वाले और आदर्शों का दृढ़तापूर्वक अवलंबन करने वाले ही इस योग्य होते हैं कि उनसे घनिष्ठता का संबंध स्थापित किया जाए। बड़ी बात दुर्जनों को समझा कर सज्जनता के मार्ग पर लाना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना उनके गिरोह को छिन्न-भन्न करने से लेकर घात लगाने की चलती प्रक्रिया में कारगर अवरोध खड़े कर देना। इसके लिए जनसाधारण को साहस जगाने वाला प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, प्रतिरोध कर सकने वाली साहसिक मंडलियों का गठन किया जाना चाहिए और सरकारी तंत्र तक यह आवाज पहुंचाई जानी चाहिए कि उसके भागीदार अधिकारी-कर्मचारी उस कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें जिसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी कंधे पर उठाई है। जनता का साहस, सुरक्षा बलों का पराक्रम और सरकारी तंत्र का समुचित योगदान मिलने लगे तो गुंडागर्दी का उन्मूलन उतना कठिन न रहेगा जितना है। हर व्यक्ति अपने को ऐसा चुस्त-दुरुस्त रखे जिससे प्रतीत हो कि वह किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है। यह कार्य एकाकी होने पर नहीं बन पड़ता, समूह में अपनी शक्ति होती है। मिल-जुलकर रहने पर आधी मुसीबत टल जाती है। निजी हौसला बुलंद रखने के अतिरिक्त अपने जैसे ही साहसी लोगों का संगठन बना लेना चाहिए और उनके साथ-साथ रहने, साथ-साथ उठने-बैठने के अवसर बनाते रहने चाहिए। वर्षों के छत्ते में शहद डालने में डर लगता है, पर वह अकेली पास आ डटे तो उसका कचूमर निकालने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है। मधुमक्खियों के छत्ते से लोग बचकर निकलते हैं। बंदर समूह में रहते हैं, और एक को छेड़ने पर दूसरे भी उनकी सहायता के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इस कारण लोग बंदरों के झुंड को छेड़ते नहीं वरन उससे बच कर ही निकलने में भलाई देखते हैं।

रीडर्स मेल

लाउडस्पीकरों से शोर बेतुका

पार्श्व गायक सोनू निगम का एक ट्वीट वर्षों पहले सोशल मीडिया में आया था, 'भगवान सबका भला करें। मैं मुस्लिम नहीं हूं और मुझे सुबह अजान से जागना पड़ता है। भारत में ये जबरन धार्मिकता कब खत्म होगी।' सोनू निगम का यह ट्वीट धर्म विशेष के खिलाफ था। बकी धर्मों के शोर का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था। मगर उस बकी को इसी गुरु वार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरा कर दिया। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म में अनिवार्य नहीं। धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों से बढ़ते शोर पर अदालत ने सख्त निर्देश जारी किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सिर्फ मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से होने वाले शोर को लेकर याचिका दायर की गई थी लेकिन अदालत ने अपने आदेश में धर्म या समुदाय विशेष का नाम न लेकर इसे सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए लागू करने को कहा। हाई कोर्ट ने कहा, 'शोर सेहत के लिए खतरा है। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि उसे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई तो उसके अधिकार प्रभावित होंगे।' मुझे लगता है कि अदालत ने तो सिर्फ इशारा भर किया है। अब इसे शक्ति के साथ लागू करने की जरूरत है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

ट्रंप की चिंता उचित

राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका पर चिंता जताते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता कर युद्ध समाप्त करना चाहिए। ट्रंप सरकार की यह अच्छी पहल है, अभी तक लंबे समय से चल रहे इस युद्ध में दोनों ओर के हजारों सैनिक, बच्चे, महिलाएं असमय काल के गाल में समा गए हैं। बमबारी से दोनों देशों की संपत्तियों का नुकसान हुआ है जिनके पुनर्निर्माण में कई वर्ष लगेंगे। युद्धबंदी नहीं की गई तो आने वाले समय में घातक हथियारों और परमाणु शस्त्रों का प्रयोग भी हो सकता है। फिर यह जंग इतनी भीषण होगी कि परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कथन में कहा भी है कि वोलोदिमिर जेलेंस्की भी समझौते पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी कहना है कि यह समय युद्ध का नहीं है। ऐसे में मानवता की भलाई के लिए विश्व में चल रहे युद्धों को रोक कर शांति की पहल करना और हथियारों पर होने वाले खर्चों पर लगाम लगा कर इस धन का उपयोग भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सहेजने के लिए किया जाना परम आवश्यक है।

संजय डागा, इंदौर

प्रगाढ़ हों इंडोनेशिया से संबंध

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की हाल की भारत यात्रा ने भारत-इंडोनेशिया संबंधों के भविष्य के बारे में महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। क्या यह यात्रा द्विपक्षीय व्यापार में पर्याप्त वृद्धि को उत्प्रेरित कर सकती है, जो वर्तमान में केवल 30 बिलियन डॉलर है? दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ाते हुए चीन से मिलने वाले भू-राजनीतिक दबावों का समाधान कैसे करेंगे? इसके अलावा, इंडो-पैसिफिक में रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा गहरी करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये पूछताछ इस ऐतिहासिक साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

अंशु भारती, बेगूसराय, बिहार
letter.editorsahara@gmail.com

बजट में खेती का रहे ध्यान

मुद्दा

रविशंकर

फरवरी 1, 2025 को पेश होने वाले आम बजट से किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलानों पर टिकी हैं। देश की कुल आबादी और श्रम बल का 70 फीसद ग्रामीण इलाकों में रहता है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना जरूरी है। बजट में खेती-किसानी को लेकर सरकार कई बदलाव कर सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र जलवायु बदलावों के चलते मुश्किल दौर में है। कृषि अर्थव्यवस्था का 15 फीसद हिस्सा है और 1.4 अरब लोगों को भोजन मुहैया कराती है। लेकिन मौजूदा समय में कृषि विकास दर घट कर 1.4 फीसद रह गई है। ऐसे में बजट कृषि क्षेत्र को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने का अहम मौका है। कृषि क्षेत्र की सकारात्मक वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था के कई सेक्टरों में मंदी का दौर है। ऐसे में कृषि क्षेत्र बढ़ता है, तो न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर भी सृजित करेगा। कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत होगा। पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र ने साबित किया है कि यह अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। खासकर प्राकृतिक आपदाओं और महामारी जैसी परिस्थितियों में।

बहरहाल, भारत में कृषि निर्यात बढ़ाने की क्षमता है लेकिन किसानों के सामने कई समस्याएं हैं। कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन, कच्चे माल की बढ़ती लागत, बंदी हुई जोत, कमजोर कृषि उपकरण, कम उत्पादकता और बेरोजगारी से निपटने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। एक अध्ययन बताता है कि जलवायु झटके मसलन सूखा, बाढ़, लू, शीत लहर आदि कृषि उत्पादकता वृद्धि में 25 फीसद तक की कमी लाए हैं। दूसरी तरफ, बीते एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनताने में वृद्धि या तो कम रही है, या फिर नकारात्मक जबकि मनरेगा के तहत रोजगार की मांग अभी भी अधिक है। उम्मीद है कि बजट में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना, मनरेगा और पीएम-आवास योजना में फंड का आवंटन बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में

मांग और निजी निवेश बढ़ाने के लिए मेहनताने में इजाफा जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है कि कृषि प्रधान देश भारत में आजादी के 77 साल बाद भी किसानों की समस्याएं दूर नहीं की जा सकी हैं।

किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य चुनौतियों के बीच संघर्ष कर रहा है। ज्यादातर किसान अपने बच्चों को खेती की जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहते। कृषि व्यवस्था में पूरी जिंदगी खपाने वाले किसान खेती को घाटे का सौदा बताते हैं। आखिर, क्या कारण है कि तमाम प्रयासों के बावजूद कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान सरकार नहीं कर पाई है जबकि भारत विश्व की टॉप पांच सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। योजनाबद्ध तरीके से कृषि में निवेश के बाद भी भारतीय किसान दूसरे देशों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। देश की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वैश्विक औसत से कम है। किसानों के असंतोष का सबसे बड़ा कारण उपज का सही मूल्य न मिलना है। किसानों के लिए नीति-निर्धारक समय-समय पर जो उपाय करते हैं, वे तात्कालिक राहत पहुंचाने वाले होते हैं। जरूरत ऐसे संरचनात्मक उपायों की है जो दीर्घकालिक हों और किसानों की समस्या को स्थायी तौर पर हल कर सकें। जैसे-यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी योजना। इससे हर महीने निश्चित आय हो सकेगी और किसान उपज को औने-पौने दामों पर बेचने को विवश नहीं होंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि बिजली-पानी, खाद, कृषि के बुनियादी ढांचे, बिपणन और जोखिमों का सामना करने की क्षमता आदि जैसी समस्याओं को ही दूर करने में हम विफल रहे हैं।

कृषि को अभी तक की सरकारें सिर्फ देश की अवाम का पेट भरने तक का ही संसाधन मानती आई हैं। कृषि के माध्यम से जीडीपी बढ़ाने पर कभी गहन मंथन नहीं हुआ। देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की समस्याएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जो सब किसानों के साथ हैं। पिछले कई सालों से खेती की लागत जिस तेजी से बढ़ी है, उस अनुपात में फसलों के दाम बहुत कम बढ़े हैं। कृषि क्षेत्र में दबाव कम करने और ग्रामीण मांग बढ़ाने की जरूरत है ताकि टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित हो सके और उत्पादक रोजगार तैयार हो सके। इससे किसानों, युवाओं और महिलाओं को लाभ होगा। बजट को गरीब समर्थक नीतियों और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के बीच संतुलन कायम करना होगा। राजस्व बढ़ाने, कर रियायत कम करने और अनुत्पादक गतिविधियों में व्यय कम करने पर काम करना होगा ताकि कृषि समर्थक लक्ष्य हासिल हो सकें।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया माता कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजमी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, स्काई लार्क, लक्ष्मीनगर, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
• समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 161
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी दायरों के लिए उत्तरदायी

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

दैनिक जागरण

जीवन की अनिश्चितता में ही उसका सौंदर्य निहित है

कांग्रेस की विभाजनकारी राह

डा. भीमराव आंबेडकर की जन्मस्थली महू में रैली करने जा रही कांग्रेस ने जिस तरह एक बार फिर इस पर जोर दिया कि संविधान पर हमला किया जा रहा है और महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है, उससे उसकी विचारशून्यता ही प्रकट होती है। कांग्रेस लंबे समय से यह माहौल बनाने में लगी है कि संविधान के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए वह हरसंभव दुष्प्रचार का सहारा भी ले रही है। यह ठीक है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उसे इस दुष्प्रचार का कुछ लाभ मिला, लेकिन वह संभवतः यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि कठ को हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। इसी कारण वह संविधान को खतरे में बताने के साथ ही इसे भी तूल दे रही है कि महात्मा गांधी के साथ डा. आंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। ये ऐसी बातें हैं, जिनका कोई मूल्य-महत्व नहीं। कांग्रेस भले ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की बातें कर रही हो, लेकिन सच यह है कि वह सामाजिक विभाजन की खाई को चौड़ा करने में जुटी हुई है। सामाजिक न्याय के नाम पर वह यह जानते हुए भी आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को खत्म करने पर जोर दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से यह कह चुका है कि आरक्षण की इससे अधिक सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। सामाजिक न्याय के बहाने कांग्रेस जातिगत जनगणना की भी मांग करने में लगी हुई है, लेकिन इस मांग के पीछे उसका उद्देश्य जातीय वैमनस्य को बढ़ाना ही है और इसकी पुष्टि उसके नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी के ऐसे बयानों से होती है कि अमुक-अमुक जाति के लोगों को दबाया जा रहा है। यह ठीक नहीं, समाज को जानबूझकर बांटने की घातक चेष्टा है।

कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करते हुए भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाने पर ले रही है, लेकिन गत दिवस ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर एक तरह से उसे नसीहत ही दी कि डा. आंबेडकर ने कहा था कि भाईचारा ही हमारा धर्म है। उन्होंने यह भी कहा कि विविधता हमारे जीवन का एक स्वाभाविक अंग है, लेकिन सभी को एक-दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हुए सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कांग्रेस भारतीय समाज की विविधता को ही वोट बैंक की सस्ती राजनीति के चलते गलत तरीके से व्याख्यायित करने में लगी हुई है। यदि कांग्रेस के रणनीतिकार यह समझ रहे हैं कि वे संविधान के संदर्भ में भय का भूत खड़ा करने और भाजपा एवं संघ के नेताओं के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से देश की जनता को बरगलाने में समर्थ हो जाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। उलटे इस क्रम में कांग्रेस की विश्वसनीयता और अधिक गिर सकती है।

अपराध और क्रूरता

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक व्यक्ति की हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव से क्रूरता ने समाज को झकझोर दिया है। जंगल में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोपितों ने अपराध को छिपाने के लिए शव को ठिकाने लगाने के लिए सिर और धड़ को अलग कर दिया था। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर अधजले धड़ और सिर को दबा दिया। पुलिस ने व्यक्ति के गुम होने की शिकायत के बाद उसकी तलाश शुरू की। पुलिस की सक्रियता से मामले का पटाक्षेप हुआ और आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

हत्या के बाद शव के साथ भी क्रूरता आरोपितों की मानसिकता को दर्शाती है

चिंताजनक है कि शांत समझे जाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्षों से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। ऊना जिला में भी एक व्यक्ति ने पिता एवं पुत्र पर गोलियां चलाकर मार डाला था। कुछ दिन पहले कुल्लू जिला में एक युवती और एक होमस्टे संचालक को भी हत्या कर दी गई थी। मनाली में विंटर कार्निवाल के दौरान एक युवक ने बहसबाजी के बाद दूसरे युवक की हत्या कर दी। सभी मामलों में आरोपित पकड़े जा चुके हैं। यह उचित है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन सक्रिय रहता है, लेकिन यह संभव नहीं है कि हर जगह पर पुलिस उपलब्ध हो। समाज के लिए यह गंभीर चिंतन का विषय है कि लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति क्यों पनप रही है? इस तरह की घटनाएं प्रदेश की संस्कृति से मेल नहीं खाती हैं। पुलिस को इस पर भी जांच करनी चाहिए कि सोलन में हत्या के बाद क्रूरता किस मंशा से की गई, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

संसदीय प्रणाली पर संकट

हृदयनारायण दीक्षित

लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के कारण बहुधा कामकाज नहीं होता। अब संसदीय समितियों की भी यही स्थिति है

अवधेश राजपूत

गत दिवस ही देश ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। भारतीय गणतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि विधायी संस्था है। संसद पर सरकार को जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी है, लेकिन काफी समय से संसद की गरिमा-महिमा पर आंच आ रही है। संसद के पास तमाम काम हैं। संसद का बहुत सारा काम समितियां करती हैं। मान जाता है कि संसदीय समितियों में राजनीतिक दलबंदी नहीं होती। ऐसे में गहन अध्ययन और विवेचन के अवसर होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अब संसदीय समितियों में भी लोकसभा और राज्यसभा जैसे हंगामे हो रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया था, लेकिन समिति की बैठकों में हंगामे की ही खबरें सामने आईं। ऐसे ही एक बैठक में पिछले शुक्रवार को भी भारी हंगामा हुआ। आरोप है कि 10 सदस्यों ने लगातार हंगामा किया। उन्हें निलंबित किया गया। समिति के प्रमुख जगदंबिका पाल के अनुसार उन्हें भी अपशब्द कहे गए। स्थिति चिंताजनक है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के कारण अक्सर कामकाज नहीं होता। अब संसदीय समितियों की भी यही स्थिति है। पूरी संसदीय व्यवस्था में अव्यवस्था है। राज्य विधानमंडल भी संसद की देखादेखी धुर अव्यवस्था के शिकार हो चले हैं। देश के सभी सदनों के पीठासीन अधिकारियों की कई बैठकें हो चुकी हैं। संसद के स्वर्ण जयंती अधिवेशन में हंगामा नहीं होने देने के लिए संकल्प लिए गए थे, लेकिन नतीजा शून्य रहा।

वक्फ अधिनियम का विवेचन कर रही जेपीसी का गठन संसद की इच्छानुसार ही हुआ है। इस समिति का इतिहास पुराना है। बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए 1987 में पहली बार जेपीसी गठित हुई। हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए 1992 में दूसरी जेपीसी का गठन हुआ। प्रतिभूति और बैंकिंग लेनदेन में जेपीसी ने जांच की। शीतल पेय कीटनाशक मुद्दे पर भी जेपीसी का गठन हुआ था। केतन पारेख शेयर घोटाला, बीआइपी चार्टर घोटाला आदि मुद्दों पर जेपीसी बनीं। महत्वपूर्ण मामलों में जेपीसी की मांग होती थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से समितियों की बैठकों में भी अराजकता बढ़ी है। वक्फ संशोधन विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। वक्फ कानून वक्फ बोर्ड को उत्पीड़क अधिकार देता है। इस कानून के अंतर्गत पीड़ित लोगों की सुनवाई की व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट है कि कानून में संशोधन देश की खास जरूरत है। विधेयक का विरोध कर रहे दल वोट बैंक तुष्टीकरण की नीति के चलते ही इसकी राह में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। वे विधेयक के प्रविधानों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं। समिति का कार्यकाल बढ़वाना पड़ा है। आखिर विपक्ष दलों के सदस्य जेपीसी की बैठकों में पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं आते? शोर शराबा और व्यवधान तर्क और तथ्य का विकल्प नहीं होते।

अनुशासित सदनों में ही व्यवस्थित कामकाज होते हैं। जबकि अव्यवस्थित सदन निराश करते हैं। संसदीय समिति प्रणाली प्रतिष्ठित रही है। यह किसी विषय के गहन विवेचन और तथ्यपरक विचार-विमर्श की आदर्श व्यवस्था है, लेकिन ऐसी समितियों के कुछ माननीय सदस्य समिति कक्ष की बैठकों में तथ्य और तर्क के साथ नहीं आते। वे समिति में भी अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। व्यक्तिगत आरोपों-प्रत्यारोपों के कारण तनाव बढ़ाते हैं। मर्यादा विहीनता का यह कार्य उस देश में हो रहा है जहां वैदिक काल में सभा और समिति प्रणाली थी। आधुनिक संसदीय समिति प्रणाली में विचारण वाले विषयों की तथ्यपरक जांच होती है। आधुनिक भारत में ऐसी समिति प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजी राज के समय 1919 के बाद हुई। पहली लोक लेखा समिति 1921 में बनी थी। लोकसभा खास प्रयोजन के लिए बजट आबंटित करती है। लोक लेखा समिति आबंटित धनराशि का उपयोग जांचती है। सीएजी प्राथमिक जांच की संस्था है। अनेक संसदीय समितियां हैं।

संप्रति संसदीय प्रणाली के अस्तित्व पर संकट है। संविधान सभा ने डा. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति बनाई थी। संविधान सभा ने उनसे अपेक्षा की थी कि वह संविधान निर्माण से जुड़ी संघ शासन समिति, प्रांतीय विधान समिति एवं मौलिक अधिकार सहित सभी समितियों के विचार मसौदे में सम्मिलित करें। डा. आंबेडकर ने संविधान सभा का मसौदा रखते हुए कहा था कि, 'भारत जैसे देश में जिम्मेदारी की छानबीन जरूरी है। प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव सहित सारी संसदीय कार्यवाही उत्तरदायी बनाती हैं। संविधान में शासन की स्थिरता के बजाय जवाबदेही को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए इसमें संसदीय पद्धति की सिफारिश की गई है।' संसदीय प्रणाली में विचार विमर्श की विशेष महत्ता है, लेकिन संसदीय हंगामे के बीच यह असंभव है। जहां हंगामा है वहां विचार विमर्श की जगह नहीं होती। कुछ दल, नेता और समूह संविधान बचाने निकले हैं। खरा देश जानता है भारत के संविधान पर कोई संकट नहीं है, पर विधायी और संविधायी अधिकारों से युक्त संसद के अस्तित्व एवं सदन संचालन का संकट है।

दुनिया में कहीं ऐसा हंगामा नहीं होता। ब्रिटिश संसद पुरानी है। अमेरिकी कांग्रेस, स्विट्जरलैंड की संघीय सभा, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जापान की डायट और फ्रांस की संसद सामान्य रूप में चलती हैं। इन देशों की कार्यवाही में हुल्लड़ और हंगामे नहीं होते। संसद स्वयं पूर्ण संवैधानिक संस्था है। इंग्लैंड के राजनीतिक विचारकों ने संसद को अपने कार्य संचालन का स्वामी बताया है। भारतीय संसद भी अपने कार्य संचालन की संरक्षक है, लेकिन सदन के भीतर अमर्यादित व्यवहार, शोरगुल और अध्यक्षीय आसन के प्रति अवमान की घटनाएं बढ़ती होती हैं। जनता चाहती है कि संसद चले। पूरे समय चले। राष्ट्रीय विमर्श हो और दलों में परस्पर सद्भाव हो। क्या यह संभव है? इसे संभव बनाने के लिए जरूरी है कि सत्तापक्ष एवं विपक्ष कार्य संचालन के मुद्दे पर एकमत हों।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई

आर के विज

जहां नक्सलवाद सिकुड़ रहा है, वहां विकास की गति और बढ़ानी होगी ताकि नक्सलियों का प्रभाव समाप्त किया जा सके

पिछले साल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। नक्सल हिंसा में कमी आने के बावजूद अभी भी 10 राज्यों में 38 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। इन 38 में 15 जिले छत्तीसगढ़ में हैं जिनमें सात अत्यधिक प्रभावित हैं। विगत वर्ष केवल छत्तीसगढ़ में 220 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, जो न केवल किसी एक वर्ष में सबसे अधिक है, बल्कि उनमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के कम-से-कम दो सदस्य भी सम्मिलित थे। हाल की गरियाबंद मुठभेड़ में 14 से अधिक नक्सलवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। उनमें कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवाद) की सर्वोच्च केंद्रीय कमेटी का एक सदस्य भी सम्मिलित है। इन आंकड़ों से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र के सिकुड़ने के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका एक मुख्य कारण केंद्रीय और राज्य सरकारों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति भी है। यह नक्सलवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह समस्या केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत है और छत्तीसगढ़ सहित समस्त प्रभावित राज्यों में बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात हैं।

विगत वर्षों में सुरक्षा बलों ने दुरूह इलाकों में कई नए सुरक्षा-कैंप स्थापित किए हैं। केवल छत्तीसगढ़ में राज्य बलों के अलावा केंद्रीय बलों की कम-से-कम 54 बटालियन तैनात हैं। राज्य के जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर बल भी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) सहित इन्हीं इलाकों में तैनात हैं, जो अधिकांशतः स्थानीय निवासी हैं, जिससे नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में मदद मिल रही है। विगत वर्ष के दो बड़े नक्सल-विरोधी आपरेशन स्थानीय सुरक्षा बलों के नेतृत्व में ही संचालित किए गए थे जिनमें कुल 64 नक्सली मारे गए। यद्यपि केंद्रीय बलों की भूमिका अग्रणी इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित करने में अति-महत्वपूर्ण है और उन्हें नक्सल विरोधी अभियानों में भी किसी भी तरीके से कम आंका नहीं जा सकता, फिर भी राज्य के सुरक्षा बलों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वे नक्सल-विरोधी अभियानों का नेतृत्व करें।

सुरक्षा बलों की मजबूत होती पकड़। फाइल

नक्सलवाद की समाप्ति के लिए आत्म-समर्पित नक्सलियों का समुचित पुनर्वास करना भी जरूरी है। केंद्र और छत्तीसगढ़, दोनों की नीतियों में आत्म-समर्पण करने वाले नक्सली को एक-मुश्त राशि देने का प्रविधान है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से पीड़ितों के साथ-साथ आत्म-समर्पित नक्सलियों को भी सरकारी नौकरी देने का प्रविधान है, जबकि केंद्र की नीति में आत्म-समर्पित नक्सलियों को कौशल-विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रविधान है। हालांकि अभी तक एक भी आत्म-समर्पित नक्सली को ऐसे प्रशिक्षण का लाभ चिह्नित केंद्रों में नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों नीतियों में बेहतर पुनर्वास के लिए कुछ संशोधन की आवश्यकता है। इन्हें जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते उन आत्म-समर्पित नक्सलियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर नौकरी के योग्य बनाया जाना जरूरी है। ऐसे प्रशिक्षण केंद्र जिला प्रशासन के स्थान पर पुलिस के संरक्षण में चलाना बेहतर होगा। आत्म-समर्पित नक्सलियों को दो कमरों का आवास भी निःशुल्क प्रदान करना जरूरी है। जो नक्सली पूर्णकालिक पार्टी सदस्य बन जाते हैं, वे आत्म समर्पण करने पर अपने गांव वापस नहीं जा सकते, बल्कि उनके परिवार-जनों को भी अक्सर वहां से भगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की नीति अनुसार एक कमरे का मकान देना पर्याप्त नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ में हाल में 'नियद-नेललानार' (आपका अच्छा गांव) योजना चालू की गई है जिसके अंतर्गत सुरक्षा-कैंप की पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त गांवों को आंगनबाड़ी, पीडीएस शप, बैंक या पोस्ट आफिस की शाखा, डिस्पेंसरी आदि 25 सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सुविधाएं लगभग 50 कैंपों के इर्द-गिर्द करीब 200 गांव को उपलब्ध कराई जाएंगी, परंतु शासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन इलाकों में नक्सलवाद सिकुड़ रहा है, वहां विकास के कार्य तेज गति से हों और प्रशासकीय एवं राजनीतिक शून्यता समाप्त हो ताकि नक्सलियों का प्रभाव समाप्त किया जा सके। यह सही है कि दंडकारण्य के कई इलाकों में जैसे मानपुर (राजनांदगांव), कांकेर, पूर्व बस्तर (कोंडागांव), दरभा, गढ़चिरौली आदि क्षेत्र में नक्सलवाद सिकुड़ा है, परंतु नक्सलियों के नए गठित 'महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़' (एमएमसी) जोन में विस्तार रुका नहीं है और दक्षिण बस्तर से भर्ती किए गए नक्सलियों की ओडिशा एवं एमएमसी जोन भेजा जा रहा है। हालांकि नक्सलियों में नई भर्ती कम हो गई है और पार्टी फंड प्रभावित हुआ है, परंतु अभी रुका नहीं है। इसी प्रकार नक्सलियों की मिलिट्री इकाइयों कमजोर जरूर हो गई हैं, परंतु उनकी बटालियन अभी भी सक्रिय हैं। बड़े नक्सली घबराए हैं, लेकिन अबूझमाड़ अभी भी उनका शरण-स्थल बना हुआ है। इसलिए जरूरी है कि सुरक्षाबल बिना कोई रणनीतिक त्रुटि करते हुए आगे बढ़ते रहें और इस निर्णायक लड़ाई को अंजाम देने में कोई कसर न छोड़ें।

(लेखक छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परोपकार

परोपकार से आशय है बिना प्रतिफल की भावना से दूसरों की भलाई करना। यह मानवीय गुण व्यक्ति को स्वार्थहीन बनाने के साथ उसके हृदय की निर्मलता और सरलता को प्रकट कर उसे सद्गुणी बनाता है। परोपकार दो शब्दों की युति है, पर यानी दूसरों की भलाई। तुलसीदास ने दूसरों की भलाई को श्रेष्ठ और दूसरों के अहित को निकृष्ट कर्म बताते हुए कहा है, 'परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई।' मैथिलीशरण गुप्त ने भी लिखा है, 'मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे।' यानी मनुष्य का काम आना ही उसकी मनुष्यता है। रहीम भी कह गए हैं, 'तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहिं न पान। कहि रहीम पर काज हित, संपति संचहि सुजान।' यानी पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते, उसी तरह सज्जन लोग दूसरे के हित के लिए ही संपत्ति संचय करते हैं।

परोपकार प्रकृति का मूल स्वभाव है। इसी कारण हवा, पानी, प्रकाश सहज रूप से सभी को बिना किसी प्रतिफल के सुलभ हैं। सत्कर्म की भावना 'कर भला तो हो भला' के भावों पर आधारित कर्म है। यानी जो कर्म किया जाएगा वही किसी न किसी अच्छाई के रूप में वापस आकर कर्ता को मिलेगा। दूसरों की भलाई में सदैव प्रवृत्त मनुष्य को इससे आत्मसंतुष्टि के साथ उसका आत्मसम्मान भी बढ़ता है, जो लोगों का उसके प्रति बढ़ते विश्वास का प्रतीक होता है। किसी को आर्थिक सहायता कर देना ही परोपकार नहीं है, बल्कि किसी के प्रति फिक्रमंद होना, उपयुक्त परामर्श देना, सांत्वना देना, सुरक्षा करना, अंगदान करना, किसी के सुख-दुख में उसके साथ खड़े होना भी इसी आदर्श गुण का परिचायक है। घर-परिवार के स्तर पर ही बच्चों में परोपकार के गुण को विकसित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बड़े होने पर वे इसे आत्मसात करते हुए परोपकारी गुणधर्मी बन सकें।

एसएन दुबे 'स्नेही'

धूल में छिपा धीमा जहर

ठौंडराज सुथार

देश में खदानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग सिलिकोसिस बीमारी के सबसे अधिक शिकार हैं

देश के कुछ हिस्सों में सिलिकोसिस की समस्या इतनी आम हो गई है कि इसे लगभग स्वाभाविक मान लिया गया है। राजस्थान, गुजरात और अन्य क्षेत्रों में खदानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग इसके सबसे ज्यादा शिकार हैं। हर दिन धूल से ढकी जिंदगियां एक अदृश्य खतरे में डूबी रहती हैं। इन कामगारों का संघर्ष केवल मेहनत तक सीमित नहीं होता। वे हर सांस के साथ उस धूल को अंदर ले रहे होते हैं, जो उनकी सेहत के लिए घातक है। यह समस्या केवल शारीरिक दर्द तक सीमित नहीं है। यह उनकी आर्थिक स्थिति, परिवार के भविष्य और समाज की स्थिरता को भी प्रभावित करती है। यह बीमारी अचानक नहीं फैलती। यह उन जगहों पर पनपती है, जहां श्रमिक सुरक्षा नियम या तो लागू नहीं होते या फिर उनका पालन नहीं किया जाता। निर्माण स्थलों, पत्थर काटने वाली फैक्ट्रियों और खदानों में काम करने वालों के लिए यह बीमारी एक ऐसी छाया की तरह है, जो हमेशा उनके साथ रहती है, लेकिन उस पर कम ध्यान दिया जाता है।

इस रोग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अकेले नहीं आता। यह अक्सर टीबी जैसी बीमारियों को भी साथ लेकर आता है। फेफड़ों की कमजोर स्थिति टीबी के जीवाणुओं के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती है। जब ये दोनों बीमारियां एक साथ होती हैं, तो पीड़ित का जीवन और भी कठिन हो जाता है। सिलिकोसिस की बीमारी पूरे तरह से रोकी जा सकती है। यह उन बीमारियों में से एक है, जिनसे बचाव के उपाय बेहद सरल हैं। कार्यस्थलों पर धूल को नियंत्रित करना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करना और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे उपाय इस बीमारी को रोक सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन उपायों को अपनाने में गंभीर लापरवाही होती है। श्रमिकों को मास्क या सुरक्षात्मक उपकरण नहीं दिए जाते। कार्यस्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय अक्सर लागू ही नहीं होते। कई बार आर्थिक दबाव या नियमों की अनदेखी से यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

नतीजतन सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति की काम करने की क्षमता धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। परिवार की आय का मुख्य स्रोत खत्म हो जाता है और आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इसके अलावा यह बीमारी परिवार के अन्य सदस्यों पर भी मानसिक और आर्थिक दबाव डालती है। इलाज के लिए लंबी प्रक्रिया और सीमित संसाधन इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। बहरहाल इस जानलेवा बीमारी के रोकथाम के लिए ऐसे उपकरण और तकनीकि विकसित की जा रही हैं, जो शुरुआती चरण में ही बीमारी का पता लगा सकती हैं। इससे समय पर इलाज और रोकथाम संभव हो सकती है, लेकिन तकनीक के साथ-साथ इस समस्या को लेकर मानसिकता में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सिर्फ भाषण से नहीं बनेगा काम

'लोकतांत्रिक मूल्यों से संवरेगा गणतंत्र' शीर्षक से लिखे आलेख के तहत गिरीश्वर मिश्र ने गणतंत्र को और मजबूत करने के लिए किए जाने वाले उपायों का विश्लेषण किया है। भारत को आजाद कराने के लिए देशवासियों ने अपना तन-मन और धन निःस्वार्थ भाव से कुर्बान कर दिया था। जिस देश में बसेरा करते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं उसके प्रति प्रेम भावना रखना भी हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। देश की रक्षा के लिए सेना के जवान दिन-रात कंपकंपाती ठंड और झुलसाने वाली गर्मी में भी डटे रहते हैं। इसी तरह हम देश के आम नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि वे देशप्रेम की खातिर अपने हर काम को ईमानदारी और नैतिकता से करें। हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं की मुख्य वजह हमारा स्वार्थ भी है। हमारा देश लगभग हर क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन हमें दिल में देशप्रेम की भावना भरनी चाहिए, भावी पीढ़ी को बचपन से ही देशप्रेम का सबक पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा देश भविष्य में भी तरक्की करता रहे। हमारे देश में राष्ट्रीय पर्वों पर विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं जिसमें कई बड़े-बड़े लोग और राजनेता भाषण देते हैं, जिसमें देश में फैली समस्याओं को समाप्त करने का जिक्र भी होता है। अगर इन बातों को भाषणों तक सीमित न रखकर जमीन पर भी उतारा जाए तो देश की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।

raju09023693142@gmail.com

मेलबाक्स

प्रगति में न आए बाधा

'प्रगति की गति' संपादकीय आलेख में उचित लिखा गया है कि बीते 75 वर्षों में देश ने जो प्रगति की है, वह समय के हिसाब से काफी कम है। एक सरकार पांच साल के लिए आती है और जनता को यह विश्वास दिलाती है कि वह पांच सालों में देश का कायाकल्प कर देगी। 75 साल में तो इस हिसाब से देश का हर व्यक्ति को करोड़पति से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं के कसिम्याई दिमाग के आगे इन 75 सालों में 60 साल तक देश के विकास ठहर गया। घोटाले दर घोटाले बढ़ते गए और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। हाल में स्थिति कुछ सुधरी है। देश में विकास का पहिया दौड़ने लगा है। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ एवं समृद्ध होने लगी है। हालांकि संविधान को खतरे में बताकर कतिपय राजनीतिक दल अपनी ओछी राजनीति चमका रहे हैं, जो अनुचित है। जिस दल द्वारा यह किया जा रहा है उसी के शासनकाल में संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती थीं। यहां तक लोकसभा में सरेआम बिल की प्रतियां फाड़ी गई थीं। भारत का संविधान आज वैश्विक स्तर पर सिर ऊंचा किए हुए लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा बता रहा है।

भुगल किशोर रक्षी, ब्रेटर नोएडा

वक्फ पर हंगामे की राजनीति

जेपीसी में वक्फ पर विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों की नीयत साफ नहीं है। विपक्षी दलों और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि उनके पास ऐसा कोई आधार और तथ्य नहीं है, जिससे वह यह सत्यापित कर सकें कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति और गतिविधियों से मुस्लिम जनमानस का कोई कल्याण हुआ है। उनका यह व्यवहार यह साफ करता है कि वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण कानून सम्मत और वैधानिक नहीं हैं। यही कारण है कि जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसद प्रतिनिधि केवल हंगामे और जोर जबरदस्ती से कार्यवाही को अवरुद्ध करना चाहते हैं, जबकि जेपीसी की मांग भी विपक्ष ने ही की थी। वक्फ बोर्डों पर राजनीतिक दलों के नेताओं का वर्चस्व है, इसलिए वह अपने अधिकार और आमदनी का जरिया खोना नहीं चाहते और किसी भी स्थिति में अवैध कब्जे छोड़ना नहीं चाहते, जबकि विभिन्न अदालतों और सरकारी विभागों ने वक्फ बोर्डों के अवैध कब्जे स्वीकार किए हैं। वक्फ बोर्ड केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए स्थापित किए गए और इसके पीछे विघटनकारी षड्यंत्र भी हैं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

73 प्रतिशत भारतीय मूल के लोग कामकाज होते हैं अमेरिका द्वारा जारी किए जाने वाले कुल एच-1बी वीजाओं से। यह आंकड़ा अमेरिका में भारतीय पेशेवरों की भारी मांग को भी दर्शाता है।

राहुल पाण्डेय
शोधार्थी, पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

आजकल

उभरती हुई वैश्विक सामरिक चुनौतियां

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह नए राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। अपनी विशिष्ट शैली में वह एक बार फिर से 'अमेरिका फर्स्ट' संबंधी नीतियों को लागू करने की दिशा में अग्रसर दिख रहे हैं। इसके साथ ही, उत्पादन एवं व्यापार समेत सामरिक मोर्चे पर भी डोनाल्ड ट्रंप चीन को पीछे छोड़ने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने में भी जुटे दिख रहे हैं। इससे नए प्रकार की वैश्विक चुनौतियां भी उभर रही हैं। लिहाजा इन चुनौतियों के प्रति भारत को अभी से ही सतर्क रहना होगा

चीन से मिल रही चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए पहले हमें स्वयं को उसके अनुरूप मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा। फाइल

आज का विश्व, विशेष रूप से एशिया, वैश्विक राजनीति और सामरिक शक्ति के मामले में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है। अमेरिका और चीन के आपसी संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देश आपस में एक तीखी प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं। दोनों शक्तिशाली वैश्विक महाशक्तियां एक-दूसरे के साथ सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं, जिससे वैश्विक संतुलन पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बदलते वैश्विक आयामों के बीच भारत जैसे देश के लिए स्वयं को सैन्य संघर्षों से अलग करते हुए दोनों और की शक्तियों से संबंध स्थापित करना होगा। इस बीच भारत को न केवल अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, बल्कि उसे यह भी तय करना है कि वह इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका किस प्रकार निभाएगा।

अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक राजनीति में कई तरह के उथल-पुथल होने की आशंका है। ट्रंप का भारत के प्रति रुख विशेष रूप से सकारात्मक रहा है, लेकिन यह भी समझ लेना जरूरी है कि ट्रंप एक व्यवसायी हैं और उनका पहला लक्ष्य स्वयं के हितों को सबसे ऊपर रखना होता है। 20 जनवरी के उनके भाषण में भारत के विदेश मंत्री को पहली कतार में बिठा कर कुछ संकेत तो दिए हैं, लेकिन ब्रिक्स देशों पर शत प्रतिशत के हिसाब से कर लगाने की बात करके उन्होंने डर को भी बढ़ा दिया कि उन पर यह भरोसा रखना कि वह भारत को सही दोस्त के रूप में मानेंगे एक बड़ी भूल होगी। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ज ने भी भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती देने की दिशा में पहला कदम उठाया। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत के सहयोग की आवश्यकता होगी और भारत को भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ सामरिक संबंधों को बढ़ावा देना होगा।

चीन की आर्थिक मजबूती : चीन ने पिछले तीन दशकों में न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि उसने अपनी सैन्य शक्ति में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। पिछली सदी के अंतिम दशक के आरंभिक वर्षों में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी, लेकिन आज चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ा लिया है। इसके प्रमुख कारण हैं- बाजारी सुधार, विदेशी निवेश आकर्षित करने वाली नीतियां और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार। चीन ने अपनी बुनियादी ढांचे की क्षमता में भी ऐतिहासिक वृद्धि की है, जैसे हाईवे, रेलवे और हवाई अड्डे, जो उसे वैश्विक स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाते हैं। उधर चीन की आर्थिक प्रगति ने उसे न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया, बल्कि उसकी सैन्य ताकत ने भी उसे अमेरिका के साथ सैन्य प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बना दिया है। चीन का सैन्य विस्तार, विशेषकर उसकी नौसेना और मिसाइल प्रणालियां, अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक नई चुनौती बन चुकी हैं।

चीन का नियंत्रित आधारित माडल : भारत और चीन दोनों ही विकासशील देशों के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन चीन की स्थिति फिलहाल कहीं अधिक मजबूत है। चीन का नियंत्रित आधारित माडल और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा प्रणाली उसे वैश्विक व्यापार में अग्रणी बनाती है। वहीं, भारत को बेरोजगारी, गरीबी और शैक्षिक गुणवत्ता की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत के कई मेधावी छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जिससे 'ब्रेन ड्रेन' की समस्या उत्पन्न हो रही है। चीन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में बड़े सुधार किए हैं, जबकि भारत में इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। फिर भी, भारत की मजबूत सांस्कृतिक धरोहर, लोकतांत्रिक प्रणाली और विदेशी नीति उसे विशिष्ट स्थान पर रखती है।

भारत की विदेश नीति में अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते बनाना जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत चीन के साथ रिश्ते खराब कर ले। भारत को चाहिए कि वह चीन के साथ भी सामरिक सहयोग बढ़ाए और सामरिक तनाव को कम करने की दिशा में काम करे। यह समय भारत के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों ही है- चीन से मुकाबला करने के बजाय उसे चीन से कुछ अच्छे पहलुओं को अपनाकर अपनी प्रगति की दिशा तय करनी चाहिए।

रणनीति में संतुलन : भारत को अब यह समझने की आवश्यकता है कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद उसे अपनी रणनीति में संतुलन बनाए रखना होगा। भारत को चाहिए कि वह अमेरिका के साथ अपने सामरिक संबंधों को मजबूत करते हुए चीन के साथ भी सहयोग बढ़ाए। इस तरह भारत अपनी स्थिति को न केवल एशिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूत बना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण, जिसमें वह शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने की बात करते हैं, यह भारत के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है। यह समय है कि भारत अपनी नीति को और अधिक प्रभावी बनाए और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूती से पेश करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

विश्व के सबसे बड़े आर्थिक और सैन्य शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा भारत के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन यह अवसर भी प्रदान करती है। भारत को अपनी विदेश नीति में न केवल शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना है, बल्कि अपने आंतरिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत अपनी शक्ति का सही से उपयोग करता है और संतुलित नीति अपनाता है, तो वह न केवल एशिया, बल्कि पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक खिलाड़ी बन सकता है।

भारत-अमेरिका के बीच संबंधों में मजबूती

मनन द्विवेदी

अमेरिकी राष्ट्रपति का पद विश्व के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक माना जाता है। ऐसे में अपनी असामान्य शैली और अप्रत्याशित व्यवहार के लिए जाने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नीतियों और आचरण के लिए अक्सर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जब हाल ही में उन्होंने दूसरी बार पदभार संभाला, तो इसने भारत के लिए संभावित असर पर भी सवाल खड़े किए हैं। भारत और अमेरिका कई साझा मूल्यों में विश्वास करते हैं, जिसने दोनों देशों के रिश्ते को दुरुस्थ लोकतंत्रों से करीबी साझेदारों में बदल दिया है। दोनों राष्ट्र लोकतांत्रिक सिद्धांतों, मानवाधिकारों, कानून के शासन और संवैधानिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ये साझा आदर्श दोनों देशों और उनके नागरिकों के बीच एक मजबूत साझेदारी की नींव रखते हैं। हालांकि ट्रंप को यह भी समझने की आवश्यकता है कि 'महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है।'' लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनकी नीतियां अलगाववाद की ओर झुकीं, जिसमें अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौतों से हाथ खींच लिया।

भारत समेत विश्व के अन्य देशों से अमेरिका आने वाले लोगों के संदर्भ में भी ट्रंप प्रशासन नए निर्णय ले रहा है। इसमें एक बड़ा बदलाव उन्होंने यह किया कि अमेरिकी भूमि पर जन्म लेने वाले सभी बच्चों की अब स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी। हालांकि भारत को अपने छात्रों और कुशल श्रमिकों के अमेरिका में बेहतर अवसरों और प्रगति के लिए प्रवास को लेकर जागरूक लोगों के कारण ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कुल एच-बनबी वीजा में से लगभग 73 प्रतिशत भारतीयों को दिए जाते हैं। यह आंकड़ा अमेरिकी कार्यक्षेत्र में भारतीय पेशेवरों की भारी मांग और उपस्थिति को दर्शाता है।

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटना एक मुख्य ध्यान केंद्रित क्षेत्र है। भारत और अमेरिका दोनों चीन की आक्रामक नीतियों को, चाहे वह साफ्ट पावर हो या सैन्य शक्ति, एक बड़ा भू-राजनीतिक और आर्थिक खतरा मानते हैं। इन दोनों लोकतांत्रिक देशों का लक्ष्य इस प्रभाव को संतुलित करना और वैश्विक मंच पर स्थिरता बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त, भारत और अमेरिका वैश्विक आतंकवाद को लेकर भी समान चिंता साझा करते हैं। वहीं भारत को उस उपक्रम को लेकर सतर्क रहना चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान इसे दिया था, जिसमें उन्होंने भारत को 'टैरिफ किंग'' कहा था। यह उपक्रम भारत की व्यापार नीतियों की ओर इशारा करता था, और उन्होंने भारत के निर्यात पर प्रतिबंध एवं अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार घाटा था।

हालांकि इन तमाम चिंताओं के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच संस्कृतिक, रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसके अलावा, भारत ने जब अपने रक्षा आयात में रूस पर निर्भरता को कम करना शुरू किया, तब अमेरिका एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। अमेरिका ने भारत को उन्नत सैन्य उपकरण जैसे अपाचे हेलीकाप्टर, चिनूक हेलीकाप्टर, एफ-16 लड़ाकू विमान और जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों की पेशकश की।

इस तरह के प्रयासों ने भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को एक नई दिशा दी एवं दोनों देशों के बीच विश्वास और साझेदारी को मजबूत किया। इस प्रकार, भारत और अमेरिका के संबंध विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में विकसित हुए हैं, जिसमें व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग ने मुख्य भूमिका निभाई है।

(लेखक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

खरी-खरी

गर्मी वाली ठंडी

इंद्रजीत कौर

एक नामचीन लेखक ने सही ही कहा है कि नाम में क्या रखा है? मौसम का नाम 'जाड़ा' हो तो जरूरी नहीं कि वह ठंडक ही दे। गर्मी भी तो दे सकता है। पसीने भी छुड़वा सकता है। यह अलग बात है कि इस तथ्य का पता अबकी ज्यादा सलीके से चला है। हो भी क्यों न? अमेरिका के जंगलों की आग, पुराने राष्ट्रपति का ही नए राष्ट्रपति के रूप में गर्मजोशी से आगमन, देश के दिल यानी दिल्ली में चुनाव की गर्माहट, गाजा में जंग का थमना, आठवें वेतन आयोग की मंजूरी आदि से पैदा हुई गर्मी जाए कहां? जाड़े को तो हारना ही था। जहां अगला हावी हो जाए तो झुकना पड़ता ही है। क्रांतिकारी सभी थोड़े बन जाते हैं।

विद्वानों का कहना है कि ग्रह, नक्षत्र, तारे और हवाओं के गठबंधन और गति में बैलेंस बिगड़ने से ऐसा हो रहा है। चाहे जाड़े में गर्मी मिले, गर्मी में जाड़ा मिले, बरसात में सूखा पड़े, बरसे में पतझड़ मिले, गरीब को और गरीबी मिले, अमीर को अमीरी की तरफ भेजा जाए तो चुपचाप सह लेना चाहिए। ऊपर वाले बने ही होते हैं मनमर्जी के लिए। चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता के समान होती है। इसका धुआं ऊपर तक चला जाता है। आपकी जला भी सकता है।

ऐसा भी हो सकता है कि जाते-जाते जाड़ा पलट जाए। बड़े-बड़े महारथी अपने कार्यकाल के अंतिम समय में पलटी मार देते हैं, तो जाड़ा क्या चीज है? पर कब तक? जब लोग अपने स्वेटर, रजाई, कोट, जैकेट वगैरह अंदर से निकाल कर फिनायल की गोली छिड़क देंगे तब? उस समय तो लगेगा कि दे-चार दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, कौन स्वेटर वगैरह अंदर से निकाले? पर यही सोच डाक्टरों की चांदी करवाएगी और हमारा सोना बिकवा देगी। इसलिए निवेदन है कि भूगोल की किताब में मौसमों के समय बदल दिए जाएं। यह भी कोई बात हुई कि बचपन से रट्टा कुछ और मरवाया जाए, जबकि वास्तविकता कुछ और हो। कितना अच्छा हो कि जो रिकार्ड में दर्ज है वह दुनिया में दिखा जाए या जो दुनिया में दिख रहा है, वही किताब में हो। पर हमारे चाहने या अर्जी देने से क्या होगा? होगा तो वही, जो ऊपर वालों की मर्जी होगी।

पोस्ट

जीवन कभी परिपूर्ण नहीं होता। सड़क की तरह इसमें भी ऊपर-नीचे जैसे कई मोड़ है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती भी है।
हरीश मिश्रा@HarrishMishrra

विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का रणजी ट्राफी खेलना बहुत अच्छी बात है। युवाओं को उनके साथ समय बिताने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह से सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है।
मोहम्मद कैफ@MohammadKaif

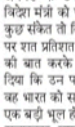

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 में अभिषेक शर्मा के बल्ले का तूफान दिखा तो दूसरे मैच में तिलक वर्मा की शानदार पारी ने भारत की नैया पार लगाई। कल का उम्दा प्रदर्शन टी-20 प्रारूप में भारतीय बल्लेबाजों में प्रतिभा की गहराई को दर्शाता है।
अजाज मेमन@cricketwallah

राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णयक फैसला किया है। जिहादी तत्वों के बढ़ते में खेल रही मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ ट्रंप ने सटीक कार्रवाई की।
अभिजीत मजूमदार@abhijitmajumder

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं?

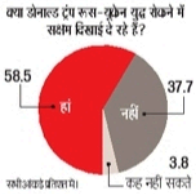

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या अमेरिकी सहायता बंद होने से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का रवैया सुधरेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

आई दिखती कुंभ मेहे गलेमर की बाढ़,
मेला तो यह माघ का पर लगता आषाढ़।
पर लगता आषाढ़ कि मौसम हुआ सुहाना,
उंडेलियां भी छेड़ रही हैं भक्ति तराना!
ले करके संन्यास बनी ममता जी मई,
समुमुक्ष ही इस कुंभ भक्ति की ऋतु है आई!!
- ओमप्रकाश तिवारी

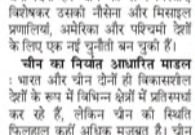

राकेश पांडेय
संपादकीय प्रभारी, प्रयागराज

अब मौन की डुबकी, लोक की गूंज

अब तक का बाचाल कुंभ, करोड़ों लोगों की गूंज का साक्षी... लेकिन अब गंगा-यमुना की लहरों से मौन का संगम होने वाला है। मौन की गूंज होगी है, लोग नहीं सृष्टि बोलेगी। अब मौन ही बाचाल रहेगा। सब कुछ सांकेतिक होगा। चलना-फिरना, विचारों का आदान-प्रदान, सबके लिए संकेत ही संप्रेषण का माध्यम बनेगा। मौनी अमावस्या आने को है। जिस दिन शब्द नहीं मौन बोलता है। आस्था का आवेग बोलता है, श्रद्धा के भाव बोलते हैं। करोड़ों की पदचाप संगीत हो उठती है और महाकुंभ अपने पूर्ण रूप में जागृत हो उठता है। मौन की डुबकी लगती है और लोक की आवाज गूंजती है- अहं ब्रह्मास्मि... हर-हर गंगे.. सनातन की धर्म ध्वजा और ऊंची होती जाती है।

सनातनी मान्यता है कि भावनाओं के संप्रेषण का सर्वाधिक रक्षितशाली माध्यम मौन है। भारतीय वांमय और अध्यात्म मौन की ऊर्जा, उसकी शक्ति और प्रभाव के उद्धरणों से भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मौन शून्य है, सनातनी मान्यता कहती है कि मौन उत्तरों से भरा पड़ा है, ''मौनं शून्यं नास्ति उत्तरैः परिपूर्णम् अस्ति।'' सनातनी मौन का भी उत्सव मनाता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि मौन उन अज्ञातों को ज्ञात कराता है जो बाचालता में छुप जाते हैं। मौन के इस गूढ़ रहस्य को उसने श्रीकृष्ण से सीखा है जो कहते हैं कि रहस्यों में मैं मौन हूं, और इसी रहस्यमयी मौन को सनातनी मौनी अमावस्या के रूप में खोलता है। सनातन की एक शाखा उन संतों की है जिन्हें विश्व 'मौनी बाबा'' के रूप में जानता है। वे उस तथ्य को बताते हैं कि मौन ऊर्जा का संचरण है, संचय है, और आध्यात्म पर वाक्, प्रवाक, बाचाल और शाब्दिक संप्रेषण का एकाधिकार नहीं है।

मौन इतना महत्वपूर्ण हो और सनातन इस पर मौन हो, यह संभव ही नहीं है। संपूर्ण विश्व में मौन का ऐसा

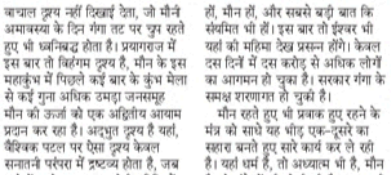

प्रयागराज महाकुंभ में रोजाना लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। फाइल

बाचाल दूरश्य नहीं दिखाई देता, जो मौनी अमावस्या के दिन गंगा तट पर चूर रहते हुए भी ध्वनिबद्ध होता है। प्रयागराज में इस बार तो विहंगम दृश्य है, मौन के इस महाकुंभ में पिछले कई बार के कुंभ मेला से कई गुना अधिक उमड़ा जनसमूह मौन की ऊर्जा को एक अद्वितीय आयाम प्रदान कर रहा है। अद्भुत दृश्य है यहां, वैश्विक पटल पर ऐसा दृश्य है जबकि सनातनी परंपरा में द्रष्टव्य होता है, जब करोड़ों-करोड़ जन एक छोटी परिधि में विद्यमान हों, लेकिन निर्वाक हों, शांत हों, मौन हों, और सबसे बड़ी बात कि संयमित भी हों। इस बार तो ईश्वर भी यहां की महिमा देख प्रसन्न होंगे। केवल दस दिनों में दस करोड़ से अधिक लोगों का आगमन हो चुका है। सरकार गंगा के समक्ष शरणागत हो चुकी है।

मौन रहते हुए भी प्रवाक हुए रहने के मंत्र को साधे यह भीड़ एक-दूसरे का सहारा बनते हुए सारे कार्य कर ले रही है। यहां धर्म है, तो अध्यात्म भी है, मौन है, तो संकेतों की बोली भी है, समझदारी है तो ठिठौली भी है। एक लंबे समय से प्रतिदिन अपने जीवनसाथी के हास-उपहास, हंसी-ठिठोली, उपदेश-निर्देश को शब्दों में सुनते आए बुजुर्ग जब उन्हें मौन में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी परेशानी तो हो ही रही है। इस परेशानी से उपजी खीझ और मोहक सी मुस्कान इस महाकुंभ में जिस शाश्वत सत्य की अनुभूति करा रही है, वह प्रेम है। यह सनातन के प्रति श्रद्धा और प्रेम ही तो है जो उनको भी संगम-तीरे दौड़ा दे रही है, यह एक-दूसरे के प्रति प्रेम ही तो है जो कृषकाय काया पर उस गठरी का बोझ भी लाद ले रहा है जिसके चलते जीवनसाथी को चलने में उलझन हो रही है।

यह प्रेम ही तो है कि कल तक जो चलना जुरूर समझते थे, मौनी अमावस्या को एक-दूसरे को सहारा देते हुए लंबी दूरी को नापते हुए ला रहे हैं। लटकती-झटकती, गिरते-संभलते, खीझते-मोहाते इस जनसमूह का आपस नयनों से होता संवाद कि 'हिम्मत मत हार भाई, कुछ ही दूर अब और बचा है'' और यह संवाद करते समय एक-दूसरे के प्रति आंखों में उमड़ते प्रेम को देख कर बरबस बिहारी याद आ जाते हैं कि ''कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन्हु ही सब बात।''

इस बार संगम तट की छटा निराली है। पिछले कई बार के कुंभ से कई गुना अधिक लोगों के जमावड़े ने महाकुंभ की रौनक बढ़ा दी है। इस मौनी अमावस्या को अगर महाअमावस्या कहा जाए तो किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि मेले में उमड़ा यह जनसमुद्र धनत्व को लेकर त्रिवेणी की तीनों नदियों से प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। मेला खचाखच भरा है, अध्यात्म का कुंभ लबालब भरा चुका है और छलकने को आतुर है। जिधर दृष्टि डालिए उधर ही नरमुंडों का प्रवाह हर बांध तोड़ने को आतुर दिखता है। फिर भी संयम है, शांति है, आवेग है, लेकिन उससे बड़ा अनुशासन है।

पवित्रता को पवित्रता की परिधि में बांधे हुए मौन रहते हुए पावनता और मोक्ष की ओर कैसे जाना है, यह यहां एकत्रित भीड़ किसी भी प्रबंधनकर्ता, विज्ञानी या विद्वान से अधिक समझती है। वैसे भी यह मान्यता है कि आज पितर और देव दोनों संगम स्नान के लिए स्वर्ग से धरती पर आते हैं। तो मौन साधना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि सनातनी परंपरा है कि पितृ और देव के समक्ष कुछ कहा नहीं जाता। कहा भी गया है कि ''मौनं सर्वार्थ साधनम्'', मौन रह कर सभी कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं।

मंथन

सुधीर कुमार
सीनियर रिसर्च फेलो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

गुणवत्ता पर असर की आशंका

यूजीसी के नए नियमों के अनुसार किसी भी विषय में नेट उत्तीर्ण करके अब किसी अन्य संबंधित विषय में भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया जा सकता हैं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल में कालेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अभी तक यूजीसी रेगुलेशन-2018 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में एक ही विषय में पढ़ाई होनी जरूरी थी। लेकिन नए रेगुलेशन के अनुसार, किसी भी शैक्षिक पृष्ठभूमि (स्ट्रीम) के युवा किसी भी विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करके या किसी भी विषय में पीएचडी करके भी उस नए विषय में विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि यूजीसी द्वारा 85 से भी अधिक विषयों में नेट परीक्षा आयोजित कराई जाती है। ऐसे में नए नियम ने युवाओं को इन सभी विषयों में अपनी योग्यता को आजमाने का अवसर प्रदान किया है। उदाहरण के तौर पर, इतिहास विषय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले युवा अब राजनीति शास्त्र, भूगोल व हिंदी या अन्य विषय में भी नेट परीक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं। इतना ही नहीं, नेट उत्तीर्ण करके वे संबंधित विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इस बदलाव का महत्व केवल नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने तक सीमित नहीं है। यह अधिक उम्मीदवारों को प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका देगा, जिससे विविधता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

यूजीसी के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। निःसंदेह, एक ओर यह कदम जहां उच्च शिक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का प्रयास करते दिखता है, वहीं दूसरी ओर इसके कई संभावित प्रभाव और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इस बदलाव से शिक्षकों की विषयगत गहराई और गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। दरअसल, किसी भी विषय में गहन अध्ययन और शोध के लिए उस विषय की बुनियादी समझ और पृष्ठभूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर यह नीति लागू होती है, तो शिक्षकों को नए विषय में दक्षता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत, समय और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई नियुक्ति प्रक्रिया यह छूट प्रदान करती है कि स्नातक या स्नातकोत्तर में रखे गए विषयों से इतर विषय में भी कैरियर बनाए जा सकते हैं, बशर्ते उस विषय में नेट परीक्षा उत्तीर्ण की जाए। इससे कई प्रकार की विसंगतियां पैदा हो सकती हैं।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस तरह चरणबद्ध ढंग से विकसित की गई है कि इसमें कक्षाओं की प्रगति के साथ-साथ ज्ञान, समझ और अनुभव का क्षेत्र भी व्यापक होता जाता है। दसवीं तक विद्यार्थी सभी विषयों को समान महत्व देकर पढ़ते हैं। दसवीं की बोर्ड परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जब विद्यार्थी को अपनी रुचि और भावी लक्ष्य के मुताबिक स्ट्रीम का चयन करना होता है। बारहवीं की बोर्ड परीक्षा तक विद्यार्थी संबंधित स्ट्रीम के अनेक विषयों का अध्ययन करता है, ताकि वह केवल एक विषय तक सिमटा न रह जाए। बारहवीं के बाद जब वह कालेज और विश्वविद्यालय पहुंचता है, तब उसे स्नातक के लिए आमतौर पर आनर्स विषय का चयन करना होता है। जिस विषय में उसे गहरी समझ व पकड़ होती है, वह उसे आनर्स के रूप में चुनता है। विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने का सपना देखने वाला युवा स्नातक के आनर्स विषय में रखे गए अपने विषय में और दक्षता हासिल करने के लिए उस विषय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई करता है।

स्नातकोत्तर तक रखे गए अपने विषय में प्राप्त शिक्षा और समझ के आधार पर वह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में शामिल होता है और फिर उसी विषय के किसी खास क्षेत्र पर शोध करने या सीधे विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता हासिल करता है। विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने की यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें एक विषय की सबसे अच्छी समझ रखने वाले युवा को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन नियुक्ति की नई नियमावली इस पूरी प्रक्रिया को महत्वहीन बनाने का काम करती दिखती है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या विषय बदलकर नियुक्ति पाने वाले शिक्षक छात्रों की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे? खासकर उन विषयों में जहां व्यवहारिक अनुभव और गहराई महत्वपूर्ण है, वहां ऐसे शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कैसे करा पाएंगे? ऐसे में नई नियमावली से शिक्षण गुणवत्ता में कमी आने का खतरा मंडरा सकता है।

यूजीसी बदल रहा भर्ती प्रक्रिया। प्रतीकात्मक

उच्च शिक्षा न केवल देश की बौद्धिक संपदा को सशक्त करती है, बल्कि यह देश की आर्थिक-सामाजिक प्रगति का आधार भी तय करती है। इस प्रणाली में प्रोफेसर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे न केवल विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं, बल्कि उन्हें शोध और नवाचार की दिशा में प्रेरित भी करते हैं। ऐसे में विभिन्न विषयों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने से विषय की गहनता और विशेषज्ञता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि स्नातकोत्तर विषय के स्थान पर नेट विषय प्राथमिकता में आ सकता है। विश्वविद्यालयों को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अधिक परिष्कृत और व्यापक चयन मानदंड अपनाने होंगे, ताकि योग्य उम्मीदवारों का ही चयन किया जा सके।